Duration Discussion. That is the second option by the Minister. We will have the Short Duration Discussion now.

श्री नीरज शेखरः सर, यह आधा घंटा पहले भी डिसाइड हो सकता था। हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, उसके लिए आधा घंटा ...**(व्यवधान)**... बिज़नेस एडवाइज़री में क्या हुआ, पता नहीं ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will have the Short Duration Discussion now. That is the sense of the House. Shri K. C. Tyagi to initiate the discussion.

SHORT DURATION DISCUSSION

Serious situation arising due to floods and drought in the country

श्री के. सी. त्यागी (बिहार) : उपसभापति महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि यहां माननीय वित्त मंत्री भी मौजूद हैं, कृषि मंत्री भी मौजूद हैं और वाणिज्य मंत्री भी मौजूद थीं। हमारी चिंताएं गांव से लेकर नैरोबी तक हैं। नैरोबी में जो घटा है, उससे भी किसान चिंतित हैं। वहां से भी, जो विकसित देश हैं और जो अमेरिका है, वह गरीब देशों पर और तीसरी दुनिया के मुल्कों पर अपनी शर्तें थोपने में लगा हुआ है।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय)** *पीठासीन हुए*]

सर, इस समय बाढ़ के दिन हैं और सूखे के भी दिन हैं। ऐसा दुनिया के कम मुल्कों में होता है कि बाढ़ भी आए और सूखा भी रहे। अभी हमने तमिलनाडु के साथियों की agony को बहुत करीब से देखा। सर, लगभग 320 से ज्यादा जिलों में अभी सूखा पड़ा हुआ है। सर, हिन्दुस्तान के विभिन्न राज्यों में पिछले साल के मुकाबले में लगभग 47 परसेंट कम बारिश हुई है और राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्णाटक, केरल, मणिपुर में 20 परसेंट से लेकर 47 परसेंट पिछले साल के मुकाबले कम बारिश हुई है। सर, कृषि मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि सूखे के कारण गेहूं की बुआई 24 लाख हैक्टेयर पिछड़ी है। ...**(व्यवधान)**...

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश)ः सर, बहुत आवाज हो रही है। ...**(व्यवधान)**...

श्री के. सी. त्यागीः उपसभाध्यक्ष जी, मैं अपना वक्तव्य दे रहा हूं और पीछे से माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आवाज सुनाई नहीं दे रही है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय)ः आप लोग शांत हो जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री के.सी. त्यागीः यह whispering campaign क्या है? Sir, what is this whispering campaign? I heard of whispering campaign in politics. Now, it has entered into the House also!

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय)ः आप शांत रहिए। ...**(व्यवधान)**... ठीक है, आप बोलिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री के. सी. त्यागीः सर, तिलहन की बुआई 23 लाख हैक्टेयर कम हुई है और कई राज्यों में रबी की फसल ही नहीं बोई गई है। महोदय, एक तरह की तकलीफ नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि यू.पी.ए. की सरकार ने स्वामीनाथन आयोग, विपक्ष के लगातार प्रयास के बाद बैठाया और स्वामीनाथन साहब इस माननीय हाउस के सदस्य रहे हैं। उस समय शरद पवार जी कृषि मंत्री थे। उस आयोग ने कुछ रिकमंडेशन्स दीं। मैं नेता सदन से कहना चाहता हूं कि आप जीएसटी के लिए दर-दर जा रहे हैं, "नगरी-नगरी, द्वारे-द्वारे ढूंढूं रे सांवरिया।" ...**(व्यवधान)**...

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजीव कुमार बालियान)ः आयोग अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बैठाया था, यूपीए ने उसका चेयरमैन बदला था। ...**(व्यवधान)**...

श्री के. सी. त्यागीः वाजपेयी जी भी हमारे नेता हैं। पहले हमारे नेता वाजपेयी जी हैं, बाद में कोई और है। आप क्यों शब्दों के ऊपर जा रहे हैं? ...**(व्यवधान)**... सर, नेता सदन ने एम.एस.पी. के लिए एक दिन भी, एक घंटा भी, एक मिनट भी... उन्होंने निजी बातचीत में हमसे कहा है कि हम आपको नहीं समझा सकते, तो अरुण जी, हम भी आपको अपनी तकलीफ नहीं समझा सकते। आपके सुधार ...**(व्यवधान)**... रवि शंकर जी, मैंने कॉल ड्राप का जिक्र नहीं किया। आजकल हम बहुत दिनों से चुप हैं, आप हमें भड़का रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय)ः आप मुझे एड्रेस कीजिए।

श्री के.सी. त्यागीः फिर आप फोन करके शिकायत करते हैं। सर, मैं चाहता हूं कि इस देश के सबसे वरिष्ठ नेता और किसान नेता शरद पवार जी यहां पर बैठे हुए हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिकमंडेशन्स थीं, जो उन्होंने भी स्वीकार कीं और इनके घोषणा-पत्र में है। पोलिटिकल पार्टीज़ के लिए घोषणा-पत्र तो holy गीता, बाइबल और कुरान की तरह से होता है। प्रधान मंत्री पद के उस समय के जो दावेदार थे, जो हमारे मित्रों राजनाथ सिंह हैं, कोई सभा नहीं थी, जिस सभा में उन्होंने न कहा हो कि भाइयो, बहनो, हमें वोट दो। हम किसानों को जो उसका लागत मूल्य है, उसमें 50 परसेंट की बढ़ोतरी करके देंगे। अच्छा है, वित्त मंत्री जी बैठे हैं, मैं इनकी जानकारी के लिए कई चीजों लेकर आया हूं।

सर, हमारी तो एम.एस.पी. एक पैसा भी नहीं बढ़ी है, लेकिन जो सातवां वेतन आयोग है, उसके बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, हम उनके खिलाफ नहीं हैं, उनका वेतन इस समय भत्तों सहित 42000 रुपये महीना है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं और 100 से ज्यादा किस्म के अलाउंसेज उनको मिलते हैं, including, shoeshine to haircut. मेरे तो हैं नहीं और आपके भी कम हैं। Shoeshine से लेकर haircut तक 100 तरह के भत्तें सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं, आप ही की रिपोर्ट के मुताबिक।

सर, स्टील, सीमेंट, साबुन, वस्त्र में पिछले 10-12 सालों में 300 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। रासायनिक खाद 300 से लेकर 1100 रुपये तक बढ़ गई है। बालियान जी, insecticides के दाम चार गुणा बढ़ गए हैं। हमें प्रसन्नता है, thanks to Mrs. Gandhi who was the Chairperson of the NAC, जिन्होंने मनरेगा में लगाकर मजदूर की मजदूरी 100 रुपये से 150 रुपये रोज कर दी, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं इसकी तारीफ करता हूं। लेकिन सोने और हीरे के व्यापारियों के, आपने अपने पिछले बजट में 70000 करोड़ रुपए घटाए थे, वह भी मुझे नागवार गुजरा था।

सर, इस समय किसान आफत में हैं। अगर यहां गृह मंत्री जी होते, तो मैं उनसे पूछता। यहां चम्पारण के हमारे नेता हैं, मैंने एक सवाल पूछ लिया तो वे मुझ से तब से नाराज हैं और हमारी नमस्ते भी बड़ी मुश्किल से लेते हैं। वे जवाब देंगे। उनको नागवार गुजरा है। सर, इस समय 40 परसेंट irrigated land है, बालियान जी 42 परसेंट कहेंगे और मैं उनकी ही बात मान लेता हूं। तो 60 परसेंट जमीन भगवान भरोसे है। आप नेशनल हाइवे बना रहे हैं। हमारे मित्र गडकरी जी नहीं हैं, वे 24 घंटे इसी में सूखे जा रहे हैं, हालांकि उनका वजन किसी और वजह से कम हुआ है। वे नेशनल हाइवे में लगे हुए हैं। मैं कहता हूं आप किसी दिन National Irrigation Highway के बारे में चर्चा कर लीजिए। ...**(व्यवधान)**... क्यों नहीं? यह अटल जी के समय में यह शुरू हुआ था। आपके प्रधान मंत्री ने भी घोषणा की थी। सर, 60 परसेंट जमीन में कुछ पैदा नहीं हो रहा है, उस के बारे में आपकी कोई चिंता नहीं है। सर, पिछले-से-पिछले साल 6000 करोड़ का ब्याज-मुक्त लोन.. मुजफ्फरनगर के हमारे साथी यहां बैठे हैं, शरद पवार जी, हमारे नेता बैठे हैं, वे मेरी गवाही देंगे कि किसानों द्वारा की जा रही आत्म-हत्या के पीछे जो सब से बड़ा कारण है, वह उसका सामाजिक अपमान है। उसकी पत्नी का जेवर, उसका ट्रैक्टर और उसके पशु, जब देनदारी के लिए सरकारी कर्मचारी जबरन वसूली के नाम पर ले जाते हैं, तब किसानों की आत्म-हत्याएं सब से ज्यादा होती हैं। सर, मराठवाड़ा में पिछले दिनों सब से बुरा सूखा पड़ा और सब से ज्यादा आत्म-हत्याएं विदर्भ और महाराष्ट्र में रिकॉर्ड हुईं। मैं बुंदेलखंड की रिपोर्ट पढ़ रहा था और इंसान होने के नाते मेरा सिर शर्म से झुक रहा था जब गरीब परिवार के बच्चे बरछली घास काटकर, उसकी बनी रोटियां खा रहे थे। यह एक हफ्ते तक एनडीटीवी पर दिखाया गया। वहां जो दोनों तरफ का बुंदेलखंड है—यू.पी. वाला भी और बुंदेलखंड वाला भी, तकरीबन 65 लाख लोगों का पलायन वहां से smart cities में हुआ, जोकि कभी बननी नहीं हैं। यह तो सपना है और इस बीच में आपने वर्ष 1994 से लेकर 2004 के बीच में सरकारी कर्मचारियों का वेतन 300 प्रतिशत बढ़ाया है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पिछले तीन सालों में एमएसपी कितनी बढ़ी है? गेहूं की 3.5 परसेंट बढ़ी है, चावल की 3.5 परसेंट बढ़ी है। सर, तीन सालों में लगातार गन्ने के दाम 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए के हिसाब से बढ़े हैं, जोकि 3.5 परसेंट भी नहीं बैठते हैं। तो आप किसका देश बना रहे हैं? सर, एक जमाना था जब हिन्दुस्तान की टोटल जीडीपी में 40-45 परसेंट का contribution रूरल इंडिया से होता था, आज वह घटकर 14-15 परसेंट रह गया है। हमारे अकाली दल के मेरे मित्र जानते हैं। एक जमाना था जब हिन्दुस्तान को हरियाणा और पंजाब से अनाज मिलता था। आप इनसे पूछिए। इनके यहां सफेद मक्खी नाम की एक बीमारी लगी है। इनके यहां एक बीघे में जहां 7-8 क्विटल कपास पैदा होता था, अब 7-8 रुपए होता है। रवि बाबू, आप जो हिन्दुस्तान बना रहे हो, एसोचैम व फिक्की जो आपके प्रिय संगठन हैं..

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : आप भी हमारे प्रिय हैं।

श्री के. सी. त्यागी : आप तो हमारे प्रिय और कारणों से हैं और आजकल कुछ कारणों से अप्रिय भी हो गए हैं। सर, उनके मुताबिक ट्रैक्टर व ट्रॉली और मोटर साइकिल की बिक्री में 20 परसेंट की कटौती हुई है। जब किसानों की क्रय शक्ति ही नहीं बचेगी, तो आपकी यह मैन्युफैक्चरिंग चाहे Made in India हो या Made in China हो, उसका करेंगे क्या? China के अंदर जो स्लम्प आया है, उसकी बड़ी वजह यह है कि ज्यादा उत्पादन हुआ है और consumer available नहीं है। आजकल आपका चीन से बड़ा दोस्ताना है। जब हमारा था, तब आप खिलाफ रहते थे। ...**(व्यवधान)**... उसका एक बड़ा कारण यह भी है। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Tyagiji, please conclude. Tyagiji, please conclude. Time is over.

SHRI K. C. TYAGI: Sir, how can the farmers' time be over? No, Sir. Sir कोई जमाना था— आनन्द शर्मा जी इसके जानकार हैं कि जब देश में लगभग 74-75 per cent कस्टम ड्यूटी लगती थी, जो आपका मुक्त बाजार आया है, market economy 'Less Government and Zero Governance'; not maximum, उसके बाद 15 per cent कस्टम ड्यूटी रह गई। मेरा आप से निवेदन यह है, यहां कृषि मंत्री बैठे हुए हैं, आप पुरानी बातों को भूल जाइए, मुझे बताइए। नेता प्रतिपक्ष के बीच वाली जो पार्टियां हैं, ये तो आप दोनों से ज्यादा गरीब किसानों के लिए हैं, लेकिन इनमें कोई विवाद नहीं है। अकाली दल वालों में भी कोई विवाद नहीं है और शिव सेना वालों में भी कोई विवाद नहीं है। जो दोनों बड़े दल हैं, जिनको नेशनल मेनस्ट्रीम की पार्टी कहते हैं, MSP पर हम क्यों नहीं बैठ सकते? क्या आप नहीं मानते कि पिछले दस-पंद्रह सालों में जो किसानों के प्रोड्यूसेज हैं, उनके दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई है? क्या फर्टिलाइजर के दाम नहीं बढ़े हैं? क्या इलेक्ट्रिसिटी के दाम नहीं बढ़े हैं, किसान को खेती के लिए जो पानी मिलता है, क्या उसके दाम नहीं बढ़े हैं? ...**(समय की घंटी)**... क्या मज़दूरी नहीं बढ़ी है, तो किसान के साथ यह ज्यादती क्यों है?

दूसरा, यह है कि जहां-जहां सूखा पड़ा है, यहां गृह मंत्री महोदय नहीं हैं, आपदा प्रबंधन के जिस तरह के इंतजामात होने चाहिए थे, वे पूरे नहीं हुए। पवार साहब सब के नेता हैं और इनसे नेताओं की शिकायत कम होती है। मराठवाड़ा में पांच-पांच सौ रुपए में एक-एक बाल्टी पानी की बिकी है, जहां बच्चों और पशुओं के बीच में फर्क करना मुश्किल हो गया है। किसका हिन्दुस्तान बनाना चाहते हैं, कौन-कौन डिजिटल इंडिया बनेगा? ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Please conclude. Tyagiji, please conclude.

श्री के. सी. त्यागी : जब यह रियल इंडिया बरबाद हो जाएगा, तो फिर इस देश में कोई डिजिटल इंडिया काम नहीं करेगा। इसलिए सबसे prime concern आप में से बहुत सारे ऐसे हैं, जो किसान राजनीति करके आए हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं, जो किसानों के वोट से जीत कर आए हैं, लेकिन मैं चाहूंगा, यह कोई मेरी चिंता नहीं है, यह रूरल भारत की चिंता है, यह असली भारत की चिंता है। आज भी उसमें 70-75 per cent लोग रूरल इंडिया में रहते हैं। इसलिए सर, यह ओडिशा की भी चिंता है और पश्चिमी बंगाल की भी चिंता है। वहां सूखा भी है और अभी पिछले दिनों वहां तूफान से बरबादी हुई है। किसानों के सवालों को लेकर, जो रूरल इंडिया की प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेकर किसान आयोग का एक सुझाव आ रहा है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): You have made your point. Please conclude. ...*(Interruptions)*...

श्री के. सी. त्यागी : मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं और सुझाव भी देना चाहता हूं। आप शरद पवार जी को किसान आयोग का अध्यक्ष बना दीजिए, हम इसका स्वागत करेंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Please conclude. ...*(Interruptions)*... Tyagiji, please conclude.

श्री के. सी. त्यागी : ये किसानों के नेता हैं, चार-पांच ...**(व्यवधान)**... अब बजट शुरू हो गया, चले गए हैं । ASSOCHAM वाले आएंगे, फिक्की वाले आएंगे, CII वाले आएंगे और उनके बाद फिर कोई और आएंगे। क्या आपने कभी किसानों के संगठनों से जुड़े हुए किसान प्रतिनिधियों को बुलाकर पूछा है...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Thank you. ...(*Interruptions*)... Tyagiji, thank you. Please.

श्री के. सी. त्यागी : कि इरिगेशन के लिए कितना बढ़ाना है? ...**(व्यवधान)**... आपको क्या करना है? आप इस सदन के अंदर तीन-तीन बार अपमानित हुए हैं, लैंड एक्विजिशन बिल लाकर। क्या आप एक बार भी MSP को लेकर बिल लाए?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Now, Dr. E.M. Sudarsana Natchiappan. मैंने आपको डबल टाइम दिया है। Please, kindly cooperate. Kindly cooperate with the Chair. ...(*Interruptions*)... I have given you double the time. ...(*Interruptions*)... No, no. Already I have given you ...(*Interruptions*)... I have given you double of the time allotted to you.

SHRI K .C. TYAGI: Sir, let me conclude. ...(*Interruptions*)... सर, मैं एक sentence में conclude कर रहा हूं। स्वामीनाथन कमीशन की रिकमंडेशन्स, जो आपने होली बुक अर्थात रामायण, गीता नहीं, बीजेपी मैनिफेस्टो है, उसमें जो लिखा है, उसको इम्पलीमेंट कीजिए। एक किसान आयोग बनाइए और किसी एक किसान नेता को, डा. गुलाटी को रहने दीजिए, वह कहीं और काम करें। आप किसी किसान नेता को उसका चेयरमैन बनाइए।

तीसरा, राधा मोहन जी, आप अरुण जी को सुझाव दीजिए कि वे इस बार किसानों, मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठ कर बजट के बारे में चर्चा करें, वरना 150 करोड़ रुपए की एक...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Please conclude.

श्री के. सी. त्यागी: सर, आप सुन लीजिए, एक रेलगाड़ी चली है, छुकछुक कर, अहमदाबाद से मुम्बई के बीच। इतने पैसे लगे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Please conclude. There are so many speakers.

श्री के. सी. त्यागी: इतने में तो हमारे गांव की सारी गरीबी दूर हो जाएगी।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): This is not fair.

श्री के. सी. त्यागी : इसलिए आप practical होकर गांव के बारे में सोचिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak on this very critical situation

[Dr. E. M. Sudarsana Natchiappan]

which is prevailing in different parts of India. On the one side, we are having the floods; and on the other, we are having parts of the country which are affected by the drought. This situation is happening every year throughout the country because India is a very big country where there is diversity of geographical locations. It has to be addressed properly by the Government of India. But, unfortunately, we always discuss every year about the disaster, about the drought, about the flood, the suffering to the people, the loss caused to the agriculturists and landless labourers and migration of labourers. Sir, many such issues are discussed every year. But the response which has to come from the Government of India is not coming. The creation of, by statute of the Parliament, the Disaster Management Commission has not been properly done. The National Disaster Management Authority, which was formed in 2005 is not working properly, according to me, Sir. It is because the recent floods in Chennai were not at all recognized by the Disaster Management System even though America had said in the NASA Report, one month in advance, that there would be a disaster in Chennai itself which will be a historical one, which will submerge many areas. So, that was the Report given by NASA. But the Disaster Management Authority, which has to prepare a Disaster Management Report in consultation with the State Government and the District level officials, and which has to constitute the Committee immediately, and take the preventive measures, did not do that. This is the question I raised in this House during the earlier debate, and now also I am putting the question to the Home Ministry whether the Disaster Management Authority is working properly or not. I even asked them to give us the chronological data through which you had asked the Government of Tamil Nadu for being prepared for the Chennai floods and the coastal area floods. But they have not given the answer in chronological order. They simply repeated whatever is possible as per the Sections of the Disaster Management Act. This is a very poor reflection on how the system is working. As per the Act, the Vice-Chairman has to be there. But there is no Vice-Chairman; there is no Scientist and there is no proper person who is looking after it or who is having the information, data and knowledge about it. And every area which is affected by the natural calamities, whether it is drought or flood, has to be captured by the system. Those areas have to be warned, through the system, by the State-level Disaster Management Authority and also the District-level and village-level committees have to be formed, and they should be prepared for everything. It includes drought also. We need not wait for the things to happen, and then we have to go for the rehabilitation. The system is very clear, Sir.

If you read Section 2 of this particular enactment, it gives a very clear thing, by saying, "Prevention of danger or threat of any disaster; (ii) Mitigation or reduction of risk of any disaster or its severity or consequences; (iii) Capacity-building; (iv) Preparedness to deal with any disaster; (v) Prompt response to any threatening disaster situation or disaster; (vi) Assessing the severity or magnitude of effects of any disaster; (vii) Evacuation, rescue and relief; (viii) Rehabilitation and reconstruction". So, these are all works to be done under Section 2 of the Disaster Management Act, 2005. But none was done in Chennai. The Central Government had not at all given any message to the Government of Tamil Nadu that they have to evacuate the people as there will be a huge flood. Therefore, you have to save them. But, 400 lives have lost because of the disaster management failure on the part of the Government of India. Now, they are going and giving charity, as if they are living in a British Government. Somebody says, "I am giving rupees five hundred crores". Next time, the Prime Minister goes and says that he is giving rupees one thousand crores. Next time, the Finance Minister says that everything will be done within four days; every banker will give loan; everyone will be rehabilitated. What is the fun we are making? People are suffering there. Even today, if you see the television, people are shouting that they are in the floods; they have not at all been evacuated from the flooded areas. Even today, the State Government does not have any strategy to do this because it is not having ...(*Interruptions*)...

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): No; no. ...(*Interruptions*)... I am sorry. ...(*Interruptions*)... What is this? ...(*Interruptions*)... No; no. ...(*Interruptions*)... You must be careful while speaking. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Please take your seats. ...(*Interruptions*)... One second, please. ...(*Interruptions*)... One second, please. ...(*Interruptions*)... Dr. Natchiappan, ...(*Interruptions*)... Dr. Natchiappan, ...(*Interruptions*)... Please listen to me.

DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: Kindly sit down. ...(*Interruptions*)... Do not expose yourself. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Dr. Natchiappan, please listen to me. ...(*Interruptions*)... Just one second. ...(*Interruptions*)... Only one second. ...(*Interruptions*)... Please do not say anything that hurts the sentiments of the other hon. Members. ...(*Interruptions*)...

DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: I have said nothing, Sir. I am just pleading for the Government of Tamil Nadu. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Okay; okay. Please continue. ...(*Interruptions*)... Please continue. ...(*Interruptions*)...

DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: I am pleading for the Government of Tamil Nadu. ...(*Interruptions*)...I am pleading for the Government of Tamil Nadu. ...(*Interruptions*)... Are you accepting it or not? ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)... I am pleading for the Government of Tamil Nadu. ...(*Interruptions*)...

SHRI T. K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, the House must hear the speech of Dr. Natchiappan. ...(*Interruptions*)... You must have patience. ...(*Interruptions*)... Especially, I request my colleagues from the AIADMK to please listen patiently and, then, reply. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Okay. You please sit down. Mr. Natchiappan, please continue. ...(*Interruptions*)...

DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: Sir, what I am saying is that the State Government is not equipped with as much facilities as the Government of India. They do not have the Air Force. They do not have naval force. They do not have the Army. They cannot have the desilting forces. Heavy machineries cannot be brought there. That is why, I am saying that it is there in Chennai itself. But the Government of India has not moved even an inch. They have not deputed the Army, which is in the Chennai city itself. Naval forces are also there. Ships are there. But they are not moved. The medical facilities are there, but they are not moved. The Air Force is there at Tambaram itself, but it is not moved. After we shouted here for four days, they just said that they would be sending the Air Force. They also provided only some cosmetic help. And, after some days, they retrieved back. What is the fun we are making? Are we taking the lives of the people of Tamil Nadu lightly? Tamil Nadu is also a part of India. The people of Tamil Nadu are also Indians. We will have to protect them. We have got a system. Had there been no system, that would have been something different. As early as 1980's, Late Shri Rajiv Gandhi had separated this department from the Department of Agriculture and brought that under the Ministry of Home Affairs so that all the forces can be united. The State Government cannot be expected to have so much of money, so much of personnel, so much of forces at their disposal. Therefore, you will have to rush all this. You should put all the mechanism, which is at your disposal, in operation. You will have to devise a mechanism to manage it. There should be a plan for disaster management. The people of Maharashtra have been affected by the drought. Are you not having any plan for them? The coastal areas of Andhra Pradesh and Tamil Nadu are always affected. Are you not having any plan for that? Why are you not implementing it? Why are you not coming forward with an effective system? It is because the NDA Government, the BJP Government, I am sorry to say, is not efficient enough to govern and help the people. That is what I

want to stress upon. You have to come forward. Don't make cosmetic changes by making announcements and letting the people suffer. Sir, people are suffering even now. The State Governments, to their limitations, are doing it. But we can't expect it unless the Central Government comes forward with all the relief. They have to go to the field and help them. People should be redeemed from the disaster. Thank you very much, Sir.

श्री बसावाराज पाटिल (कर्णाटक) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जैसा अभी थोड़ी देर पहले त्यागी जी ने बताया है, भारत के लगभग आधे जिलों के अंदर अकाल या फ्लड की स्थिति है। देश के अन्य भागों में किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है, विशेषकर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और अन्य भागों के अंदर तो जो लगातार कई सालों से आत्महत्या की समस्याएं चल रही हैं, वह हम अपनी आंखों से देख रहे हैं।

महोदय, जब ड्रॉउट की सिचुएशन आती है तो कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जहां तक मेरे कर्णाटक प्रांत का सवाल है, जो उत्तर कर्णाटक है, वहां पर तुअर होती है, जो भारत का सबसे बड़ा तुअर का प्रोडक्शन सेंटर है। वहां से रोज कम से कम 50 टर्क तुअर जाती है, लेकिन आज वहां पर तुअर का प्रोडक्शन एक चौथाई से भी नीचे चला गया है और उसके ऊपर लागत, खर्च और समय सबसे ज्यादा लगता है। इसलिए आज वहां के किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है और वे रूखी-सूखी जमीन पर खड़े हैं। उसके साथ ही चना, गेहूं और ज्वार है और ज्वार न होने के कारण जानवरों को खाने के लिए जो चीज मिलती है, वह भी उनको नहीं मिल रही है। अभी किसान अपने जानवरों को बेच रहे हैं, क्योंकि उनके पास उनको खिलाने के लिए चारा नहीं है। कई सालों के बाद पहली बार उत्तर कर्णाटक के अंदर इस प्रकार की बड़ी दयनीय स्थिति का निर्माण हुआ है, विशेषकर बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, यादगीर, बीजापुर, कोप्पल, बागलकोट और बेलगाम के कुछ हिस्सों में हैं। महोदय, अगर इस प्रदेश में युद्ध स्तर पर आने वाले पांच-छः महीनों के लिए और अप्रैल तक, अगली फसल आने तक, अगर जानवरों के चारे और पीने के पानी के लिए और विशेष प्रयास नहीं किया जाएगा तो इसका गंभीर परिणाम देखना पड़ेगा। किसानों के पास जो ताकत है, उन्होंने उसे, अपने सारे जानवरों को आज बेचना शुरू कर दिया है। चारा नहीं मिलने के कारण किसान एक विशिष्ट परिस्थिति के अंदर जी रहे हैं। मैं सरकार से विनती करता हूं कि कर्णाटक की सरकार ने लगभग 23 हजार करोड़ रुपए का एक प्रपोजल भारत सरकार के पास भेजा है। मैं यह भी जानता हूं कि पिछली बार जब इस प्रकार का सर्वे हुआ उस समय की हानि को लेकर भारत सरकार ने एक हजार पांच सौ करोड़ रुपए के रिलीज़ की घोषणा की। लेकिन मुझे जो जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार वहां की सरकार कहती है कि वे पैसे हमको अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो मैं फिर से माननीय मंत्री जी से विनती करता हूं कि वे इन बातों की ओर ध्यान दें, विशेष इंस्पेक्शन करने के लिए भारत की सरकार की टीम उत्तर कर्णाटक में फिर से एक बार जाए। जो आने वाले 7-8 महीने तक, जून के महीने तक आने वाली गंभीर परिस्थिति में जो-जो संकट आते हैं, उन्हें पार करने की दृष्टि से भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी के नाते उसे जो भी काम करना है, वह करे, वहां की राज्य सरकार का साथ दे और सारे उत्तर कर्णाटक के किसानों के आंसू पोंछने का काम करे।

4.00 P.M.

महोदय, भारत एक ऐसा देश है, जो विश्व में सबसे ज्यादा अनाज पैदा करता है। इसकी पोटेंशिएलटी इतनी है कि अगर यह चाहे तो दुनिया के 250 करोड़ लोगों को अन्न दे सकता है परन्तु आज हम दयनीय स्थिति में हैं। कुछ सदस्यों ने बताया कि हमारी कोई दूरगामी योजना नहीं है। जैसा आदरणीय त्यागी जी ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर जैसे नियमित वेतन आयोग बनते हैं, जैसे अन्य चीजें नियमित होती हैं, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में जब चर्चा चलती है, उसी स्तर पर किसानों के भविष्य के बारे भी अगर सोचने की कोई व्यवस्था बनेगी, तब ही यह देश दुनिया को अन्न भी दे सकता है और अपने आप भी गौरव से रह सकता है। इसीलिए आवश्यकता पड़ने पर सरकार आयोग की रचना करे और जिन-जिन चीजों की तरफ उसे ध्यान देना चाहिए, उन सबकी तरफ वह ध्यान दे।

महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। कई बार इंश्योरेंस की नीति बनती है। किसान इसमें दस-दस सालों से पैसा भरता है, जब इस प्रकार का संकट आता है, तो इंश्योरेंस कम्पनी कानून का कोई-न-कोई बहाना लेकर उनको इंश्योरेंस का पैसा नहीं देती है। अगर 100 लोगों ने इंश्योरेंस कराया है, तो केवल 10 लोग ही उसका फायदा ले पाते हैं, बाकी 90 लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनका दिया हुआ पैसा भी चला जाता है और इस प्रकार के संकट की घड़ी में उनको जो न्याय मिलना चाहिए, उससे भी वे वंचित रहते हैं । ऐसी स्थिति में मैं सरकार से विनती करता हूँ कि आने वाले दिनों में इस उत्तर कर्णाटक में भयंकर पानी की समस्या होगी, जो आज ही से प्रारंभ हुई है। आज कई जगह टैंकरों से पानी भेजने की स्थिति का निर्माण हुआ है, तो आने वाले मई महीने तक इसकी स्थिति क्या होगी, इसकी गंभीरता को सरकार समझे।

महोदय, एक ज़माना था, जब भारत में एक आदमी के पीछे 15 पशु थे और आज 15 आदमियों के पीछे एक पशु है। अगर वह भी चला जाएगा, तो भारत की आत्मा जो गाय पर निर्भर है, जिसकी हर चीज सोने के समान मानी जाती है, अगर उसकी रक्षा नहीं की जाएगी, तो आने वाले दिनों में ये गायें वगैरह हमारे बच्चों के लिए exhibition की वस्तु बन जाएंगी, जो हमारे भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर पशु संपत्ति मरेगी, तो इसका पाप देश को लग सकता है, इसलिए हमारे कृषि मंत्री जी उस ओर तुरंत ध्यान दें और एक भी गाय इस प्रकार के संकट में पड़े, एक भी गाय पानी के अभाव में, चारे के अभाव में मरे, इस प्रकार की बात सुनने को न मिले, इस दिशा में तीव्रता से सरकार अपना काम करे, मैं यह विनती करता हूँ।

महोदय, वैसे भी उस प्रदेश के अंदर लगभग 600 दाल मिलें चलती हैं। उनके सारे धंधे बंद हो गए हैं। जब किसी कारण देश-विदेश की व्यवहार नीति में तुअर दाल की कीमत एकदम ऊपर यानी 200 रुपए प्रति किलो हुई, तब सरकार की तरफ से रेड पड़ी। जहां से रोज दस ट्रक दाल भेजते थे, वहां पर सरकार द्वारा रेड करने पर पूरे प्रदेश में 400 थैले भी नहीं मिले। ईमानदार होकर व्यापारी भी परेशान होते हैं, छोटा-मोटा धंधा करने वाले भी परेशान होते हैं। ऐसे समय में सरकार कोई नीति बनाए ताकि इस प्रकार के दाल मिलों के सहारे अपनी जिदगी का गुजर-बसर करने वाले जो लेबर हैं, उनको सरकार एक विशेष प्रकार का पैकेज दे ताकि वह मिल चले। यह काम वह कहीं से माल मंगा कर करे, इस दिशा में सोचना भी अत्यंत आवश्यक है।

महोदय, गेहूं और चने की भी बहुत अधिक क्षति हुई है, कपास का भी बहुत अभाव हुआ है। प्रारंभ से ही कपास डाला गया, लेकिन हर साल जो कपास आता था, उसके पाचवें हिस्से का एक हिस्सा भी कपास इस बार नहीं है। इन सब चीजों को सरकार के ध्यान में लाते हुए मैं जरूर यह विश्वास करूंगा कि हमारी सरकार बहुत गंभीरता से इस प्रकार का जो अकाल है और जो अतिवृष्टि है, इन चीजों को सीरियसली लेगी।

महोदय, साथ ही साथ, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जिस समय चने के ऊपर इस प्रकार का संकट आया, वहां की राज्य सरकार को भारत सरकार ने सभी प्रकार से सहायता दी है... पूरा उसने कोई नहीं किया। यह जो अपादान है, ठीक है। विमान की सेवा दी गई, हेलिकॉप्टर की सेवा दी गई, सेना को भेजा गया, शहर के अंदर नावें छोड़ी गईं, उसकी तरफ से जितना हो सकता है, जो सरकार की जिम्मेदारी है, वह भी सरकार ने करने की कोशिश की है। कुछ भी नहीं किया गया है, यह कहना ठीक नहीं होगा। इस प्रकार की कई बातों को लेकर मैं माननीय मंत्री जी से विनती करता हूँ कि भारत के अन्य भागों में यानी महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार, विशेष कर जो बुंदेलखंड प्रदेश है, जिसके कुल 13 जिले पड़ते हैं, वहां की आबादी लगभग 2 करोड़ है, आज उनकी दयनीय स्थिति है। वे रोजगार के लिए, खाने के लिए, काम के लिए पलायन कर रहे हैं। बुंदेलखंड के लोग बाहर जाकर सारे देश की सेवा करते हैं, लेकिन वहां की जनता भूखी मर रही है, यह सुनने से मन में वेदना होती है। विशेषकर, बुंदेलखंड प्रदेश के उन गरीबों के हितों के बारे में सरकार ठीक से सोचे कि वह उत्तर प्रदेश का हिस्सा होगा या मध्य प्रदेश का हिस्सा होगा। इन दोनों भागों के पूरे 13 जिलों की जनता के हित के बारे में हमारे कृषि मंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिए, मैं ऐसी विनती करता हूँ।

मैं एक बार फिर सरकार से यह विनती करता हूँ कि समय और प्रसंग की गंभीरता को समझते हुए माननीय मंत्री जी, जो यह संकट है, विशेषकर लोन देने की जो नीति है, उस पर आप ध्यान दीजिए। कई बार मुझे किसान कहते हैं कि इतनी बड़ी जो नीति होती है, जिसमें कभी-कभी यह कहा जाता है कि सरकार की तरफ से सूद माफ कर दिया गया, लेकिन कई किसान यह कहते हैं कि हमको लोन देते समय ही कम से कम सूद रखिए, तीन परसेंट रखिए, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन रेट ज्यादा रखते हैं, बीच में कभी माफ करते हैं। इसके कारण हमें ईमानदार होते हुए भी सरकार की दया पर जीने देने की जो कोशिश की जा रही है, उसका कई किसान विरोध कर रहे हैं। इसलिए अगर सरकार सूद देने की नीति में भी परिवर्तन कर किसानों को कम से कम ब्याज पर अपने कृषि संबंधी कार्यों को करने में सहायता करेगी तो उससे किसानों को लाभ होगा।

कई बार यह सुनने से मन में विडंबना लगती है, जैसा के.सी. त्यागी जी ने कहा, अगर कोई कार लेना चाहता है तो कहते हैं कि "वॉक-इन" आओ और बाहर जाते समय कार लेकर जाओ। अगर किसान जाएगा या 10-20 हजार की पूँजी वाला फुटकर व्यापारी जाएगा, तो उसे क़ानून के कई संकटों को पार करना पड़ेगा। जिस प्रकार उन लोगों को सुविधा है, वैसे ही छोटे धंधे करने वाले या इस प्रकार के किसानों को सरकार की तरफ से सब प्रकार की सुविधा देने की जरूर कोशिश होनी चाहिए। जल, जमीन, जंगल, जानवर, ये सृष्टि की मूल संपत्ति है। अगर इनका विनाश होगा, इनमें कुछ हेर-फेर होगा, तो भारत की कोई भी अर्थ-नीति इस देश को नहीं बचा सकती है। इसकी गंभीरता को समझते हुए माननीय मंत्री जी तीव्रता से कोई ऐक्शन लेकर

[श्री बसावाराज पाटिल]

भारत के उन सभी 320 जिलों के लिए, जो अलग-अलग प्रकार के संकटों को झेल रहे हैं, कोई ठोस कार्रवाई करें। इसके साथ ही, "किसान आयोग" के बारे में जो कहा गया है, उसके बारे में गंभीरता से सोचकर उसका जल्द से जल्द गठन करें। इस प्रकार की अपेक्षा माननीय मंत्री जी और सरकार से करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ,

धन्यवाद।

डा. चंद्रपाल सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आज आपने मुझे सूखे की विषम परिस्थितियां विषय पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा।

मान्यवर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से किसानों पर निर्भर करती है। किसान आज बुरे तरीके से आफत में है। किसान आज बुरे तरीके से परेशान है। कभी सूखा तो कभी बाढ़, कभी ओलावृष्टि तो कभी आँधी और तूफान, सारी आपदाएँ किसान के ऊपर आती हैं। आज किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी और भारत सरकार से यह निवेदन करना चाहूँगा कि आज किसान ही क्यों आत्महत्या कर रहा है? आज कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति आत्महत्या क्यों नहीं करता? आज कितने इंजीनियर्स ने आत्महत्या की है? आज कितने डॉक्टर्स ने आत्महत्या की, कितने दुकानदारों ने आत्महत्या की, कितने उद्योगपतियों ने आत्महत्या की? आज किसान भुखमरी के कगार पर पहुँचकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है, क्योंकि किसान खेती के लिए ऋण लेता है और जब फसल बरबाद हो जाती है तो वह उस ऋण को वापस नहीं कर पाता। उसको अपने घर में बच्चों की पढ़ाई-लिखाई भी देखनी है, उसको अपनी बेटी के हाथ भी पीले करने हैं, उसको अपने बूढ़े बाप के इलाज का प्रबंध भी करना है। वे तमाम व्यवस्थाएं जो साल भर की हैं, जब पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती हैं, तब किसान मजबूरी में एक रास्ता अपनाता है और आत्महत्या करता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि उसे इस रास्ते पर जाने से रोका जाए। आज पूरा उत्तर भारत सूखे की चपेट में है। वैसे तो देश के लगभग आठ राज्य सूखे की चपेट में हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा भाग सूखे की चपेट में है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 50 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है और भारत सरकार से मदद मांगी गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जब उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि हुई थी तब उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से सहायता की मांग की थी और भारत सरकार ने ऐलान भी किया था कि 13 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर के हिसाब से किसानों को मुआवज़ा दिया जाएगा। मैं इस सदन में बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से तो प्रदेश के किसानों को मुआवजा दिया, लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिली, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज सूखा पड़ा है और उसके हालात इतने गम्भीर हैं कि लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। मैं जिस क्षेत्र बुन्देलखंड

से आता हूं, वहां आज एक-एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। वहां एक तरफ तो खरीफ की फसल पूरी तरह नस्ट हो गई है और दूसरी तरफ रबी की फसल भी लोग नहीं बो पा रहे हैं।

मान्यवर, पूर्व कृषि मंत्री, श्री शरद पवार जी हमारे बीच में मौजूद हैं। उनके कार्यकाल में बुन्देलखंड को एक पैकेज मिला था। उसके माध्यम से बुन्देलखंड में पानी उपलब्ध कराने के लिए तमाम तरह से संसाधन जुटाने के प्रयास किए गए थे, जिनमें तमाम चैक डैम्स बनाए जाने की व्यवस्था थी और जहां एक ओर सिंचाई के संसाधनों का विस्तार करने की व्यवस्था थी वहीं दूसरी तरफ बड़े-बड़े तालाब बनाए जा रहे थे। वहां मंडियां बनाई जा रही थीं। तमाम विकास के कार्य हो रहे थे। उन विकास के कार्यों की वजह से बुन्देलखंड के लोगों में कुछ आशा बंधी थी और वे सोचते थे कि आने वाले दिन उनके लिए खुशहाल होंगे, लेकिन मान्यवर, बुन्देलखंड का वह पैकेज आने वाले वर्षों में पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। बुन्देलखंड के पैकेज को रोक दिया गया है। इसलिए मैं, इस सदन के माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि माननीय मंत्री जी पूरी तरह से किसान के पुत्र हैं, वे किसान परिवार से निकले हुए व्यक्ति हैं, वे किसान की पीड़ा को अच्छी तरह से समझते हैं कि बुन्देलखंड का पैकेज, जो सरकार की तरफ से स्वीकृत किया गया था, जिसे रोक दिया गया है, उसे भारत सरकार की तरफ से तत्काल रिलीज किया जाए, जिससे वहां विकास के कार्य हो सकें और वहां के लोगों को लाभ मिल सके।

माननीय सभापति जी, यह मामला कोई एक दिन का नहीं है। एक तरफ बरसात होती है, दूसरी तरफ बाढ़ आती है। यह जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रायः हर वर्ष होता है और इस प्रकार से यह एक स्थाई व्यवस्था हो गई है। मैं बुन्देलखंड की बात कहता हूं कि वहां कोई वर्ष ऐसा नहीं जाता, जब वहां रबी की फसल की बुवाई होनी होती है, तो वहां सूखा पड़ जाता है और जब किसी तरह से फसल पक कर तैयार होती है, तो उस वक्त कभी ओले पड़ जाते हैं और कभी तूफान आ जाता है। पिछले पांच वर्षों से बुन्देलखंड के किसानों के घरों में फसल का दाना नहीं जा पाया है। वे बुरी तरह से परेशान हैं। ऐसी स्थिति में अगर किसान आत्महत्या नहीं करेगा, तो क्या करेगा?

मान्यवर, इसीलिए मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां आज सूखा भी पड़ रहा है और दूसरी तरफ से बाढ़ भी आ रही है, इसलिए अब वहां स्थाई व्यवस्था करने की आवश्यकता है। अतः भारत सरकार को इस बारे में एक 'नेशनल एक्शन प्लान' यानी एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है, जिसमें तमाम बिन्दुओं पर गौर करने की आवश्यकता है। आज जो सूखा पड़ता है, जो ओला पड़ता है, जो तूफान आता है, उसकी जांच के लिए यहां से एक दल जाता है। मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अधिकारियों का दल उस क्षेत्र में जाकर न तो सूखे का आकलन कर सकता है, न बाढ़ का आकलन कर सकता है, न ओलावृष्टि का आकलन कर सकता है। हमें पूरी तरह से नौकरशाही पर आधारित नहीं रहना चाहिए। हमें कुछ इस तरीके के नॉर्म्स बनाने चाहिए क्योंकि यह भी होता है कि एक गांव में सूखा पड़ता है, पता लगता है कि एक गांव में ओला पड़ गया और दूसरे गांव में ओला नहीं पड़ा और एक गांव का नुकसान हो गया। आप जब सर्वे करते हैं तो देखते हैं कि पूरी तहसील में सूखा पड़ा है या नहीं पड़ा है, पूरी तहसील में ओला पड़ा है या नहीं पड़ा है और उसके आधार पर आप उनको मुआवजा देने का काम करते हैं। हम आपसे

[डा. चंद्रपाल सिंह यादव]

सदन के माध्यम से यह निवेदन करना चाहते हैं कि नौकरशाही के हस्तक्षेप को समाप्त करके आपको किसानों की एक टीम बनानी चाहिए जो वहां जाकर जनपद का स्वयं सर्वेक्षण करके सरकार को दे और सरकार को उसे स्वीकार करना चाहिए।

मान्यवर, बीमा का प्रावधान तत्काल लागू होना चाहिए। आज किसान बीमा लेता है। जब वह ऋण लेने के लिए जाता है तो तमाम बीमा कम्पनियां पहले से प्रीमियम काट लिया करती हैं। उन्हें बीमा का प्रीमियम तो लग जाता है, लेकिन सूखा पड़ गया या ओला पड़ गया तो उनका बीमा किसानों को नहीं मिलता है। पिछले वर्ष में जब ओले पड़े थे, उस समय के ओला पीड़ित किसानों का बीमा आज तक उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाया है। किसान फाइल लेकर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें बीमा नहीं मिल पा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक्शन प्लान में मौसम विभाग की सूचना के आधार पर तमाम घोषणाएं की जानी चाहिए। अगर किसान को पहले से पता हो कि इस साल सूखा पड़ने वाला है, इस साल बाढ़ आने वाली है, इस साल तूफान आने वाला है तो वह उसकी तैयारी कर सकता है। हम तो परम्परागत खेती कर रहे हैं। हम तो गेहूं बोते हैं, हम तो धान बोते हैं, हम तो चना बोते हैं, लेकिन इन सब में पानी की आवश्यकता होती है। अगर पानी नहीं मिल पाता है तो फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। हमें नयी तकनीक के आधार पर खेती करने के लिए किसानों को जाग्रत करना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन है ...**(समय की घंटी)**... या अन्य तमाम प्रकार की नयी तकनीक के आधार पर तैयार किया हुआ बीज, जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो, अगर वह किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा, तो निश्चित रूप से किसान अच्छी खेती कर पाएगा। सूखा या बाढ़ के मौके पर किसान को जिंदा रहने के लिए, उसका पेट भरने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार की तरफ से उसे मदद उपलब्ध करायी जाए। आज लोग खेती छोड़कर भाग रहे हैं, वे खेती नहीं करना चाहते क्योंकि खेती करने वाले से ज्यादा आमदनी रिक्शा चलाने वाले की है। तमाम लोग रिक्शा चलाने के लिए दिल्ली आ जाते हैं, मुम्बई चले जाते हैं। हमारे क्षेत्र में तमाम बुन्देलखंड के लोग अपना-अपना क्षेत्र छोड़कर, वहां से पलायन करके रोजगार के लिए दिल्ली, मुम्बई और आस-पास घूम रहे हैं, वहां रोजगार पाने का काम कर रहे हैं, जिससे उनका पेट भर सके, उन्हें खाना मिल सके। इसलिए मैं आज सदन के माध्यम से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि किसानों की आज जो दुदर्शा है, किसानों पर जो आफत है, किसान जिस परेशानी में हैं, उसके लिए आपको मदद करने की आवश्यकता है। आपको उनकी मदद करनी चाहिए और उन्हें तमाम वैकल्पिक संसाधान उपलब्ध कराए जाने चाहिए जैसे फूड प्रोसेसिंग के लिए अगर गांव में इकाई स्थापित की जाए तो अगर खेती नहीं होगी तो कम से कम प्रोसेसिंग के माध्यम से, जो थोड़ा बहुत पैदा किया, किसान आमदनी कर सकता है। किसान पशुपालन कर सकता है। अगर अच्छी डेयरी स्थापित की जाए, किसान के दूध की सही कीमत अगर उसे मिले तो वह दूध का उत्पादन करके अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकता है। आज कहीं पानी है भी तो उसका कोई प्रबंधन नहीं है। हमारे यहां नदियां हैं, पानी आता है, लेकिन बरसात के समय पूरी तरह से बहकर निकल जाता है। उसका प्रबंधन ठीक तरीके से नहीं हो पाता। हम सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि जो बुन्देलखंड पैकेज दिया गया था, उत्तर प्रदेश और बुन्देलखंड क्षेत्र के लिए, अगर बुन्देलखंड पैकेज का पैसा उपलब्ध कराया जाएगा तो निश्चित रूप से नदियों के माध्यम से जो पानी आता है, उसका प्रबंधन हो सकता है। बड़े-बड़े तालाबों में पानी भरकर

उसे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है, चैकडैम बनाकर उन्हें पानी की सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है। आज किसानों के सामने जो गंभीर समस्या है, उसका हल केवल एक ही है कि उसकी मदद के लिए हम लोगों को सोचना पड़ेगा, हमें विचार करना पड़ेगा, सरकार को विचार करना पड़ेगा। सरकार अगर सोचेगी, सरकार अगर संसाधन उपलब्ध कराएगी, प्रदेश की सरकारों को मदद करने का काम करेगी...। आज सूखाग्रस्त क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की माननीय अखिलेश यादव की सरकार अपने संसाधनों से किसानों की मदद करने का काम कर रही है। वह गरीब किसानों को संसाधन उपलब्ध कराने का काम कर रही है। मैं इस सदन के माध्यम से भारत सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को कम से कम दस हजार करोड़ रुपये का पैकेज मिलना चाहिए, जिससे कि वहां के सूखे से निपटा जा सके, वहां के किसानों की मदद की जा सके, वहां पर जो अभावग्रस्त क्षेत्र हैं, उनमें संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें । इसलिए हम आज इस सदन के माध्यम से आपसे यह निवेदन करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Thank you. Now, Ms. Dola Sen.

MS. DOLA SEN (West Bengal): Hon. Vice-Chairman, Sir...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (Uttar Pradesh): Is it the maiden speech? ...(*Interruptions*)...

MS. DOLA SEN: No. ...(*Interruptions*)... Let me tell. I am very happy to be here as a new Member of this House for the last few months, and, I am thankful to you for having given me the opportunity to participate in this Short Duration Discussion.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Is it your maiden speech?

MS. DOLA SEN: Sir, let me begin with a request not to treat it as my maiden speech; not because the subject is not so important but because of the limited time...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): All subjects are important. ...(*Interruptions*)... All subjects are important here.

MS. DOLA SEN: Sir, it is not because the subject is not important. I am not telling that the subject is not important. The subject is very important but because of the limited time, which we have for this discussion. Thank you, Sir.

Flood and drought are the two words which bring misery to millions of our fellow Indians. There are many States in India which are prone to flood and there are many other States which are prone to drought.

Mr. Vice-Chairman, Sir, as per nature's wish, I come from the State of West Bengal, and, it is one out of only five or six States which suffer from both flood

[Ms. Dola Sen]

and drought. Let me first re-assure everyone in and around Chennai, who experienced the nature's fury and trauma a few weeks ago. The thoughts and prayers of Bengal are fully with them.

Coming to West Bengal floods, cyclone Komen hit in July, August; 100 lives were lost and 61 lakh people were affected. As far as Damodar Valley is concerned, West Bengal is located in the downstream of major rivers including Damodar. Flood control was the primary objective for constructing various dams in the Damodar Valley area. This has taken a backseat and other activities like power generation and supply of water have taken precedence. If we talk about sudden release of water, when cyclone Komen hit, in three days, the DVC dams discharged 1.30 lakh cusecs of water. No proper monitoring mechanism is there. Sudden release of water led to manmade flooding and loss of many lives. DVC dams need to be upgraded so that their storage capacity can meet the objective of controlling floods. Prolonged neglect can cause another substantial disaster in the State.

Regarding action taken by the State Government during recent floods plus Darjeeling landslides, the State Government had an opening balance of ₹ 610 crore in the SDRF. Additional 387 crore of rupees were received from the Centre. So, expenditure of 937 crore of rupees has already been made out of the SDRF leaving a balance of ₹ 59.82 crores only. The State Government has also spent ₹ 1,000 crore out of its own resources. Our request is that the NDRF funds should be released to meet the requirements of immediate relief and restoration works. Thirteen lakh hectares of agricultural land is inundated. Consider a programme of loan waiver, restructuring and grant of fresh loans to farmers.

Now coming to droughts, West Bengal has experienced an unprecedented prolonged dry spell since September, 2015. Lack of rainfall has adversely affected standing paddy crops in four districts — Burdwan, Purulia, Bankura and West Midnapore. An advisory has been prepared and issued to sensitise the farmers about the judicious use of available water for Rabi and Rabi Summer crops and selection of right crops for coming cropping seasons. Approximately 2025 metric ton of seeds for Rabi and Rabi Summer crops -- Boro, wheat, mustard, sunflower, groundnut, toria, seasame, maize, etc. -- have been supplied to three districts. ₹ 387 crores have been released from SDRF. The State's demand was ₹ 6,000 crores due to the flood and ₹ 4,000 crores due to the drought. What is the system of allotment of money? The Central team goes and comes back, but, very unfortunately, the amount that is decided is not fixed in consultation with the Chief Minister of the States. Irrigated land is 40 per cent of the total farm land and hence drought affects the farmers very adversely and hence greater harm, and the result is reduced agricultural yields, inflation, rise in farmer suicides.

As interventions — I&W Department extended surface water supply, utilizing the maximum volume available from different river valley projects and special allocation from DVC even by purchasing water from Tenughat, Jharkhand, at a cost of Rs. 15 crores. WBRIDD has taken care to restore all their installations and kept these functional on war-footing steps. Availability of water for irrigation in DVC system is low for the coming season. Situation is under close watch. All concerned Departments, Agriculture, Major and Minor Irrigation, Food Supplies, Power, etc., have been advised to mobilize their resources to help farmers cope with the situation.

For reference, I have two letters of August 7th and August 10th of our hon. Chief Minister of West Bengal to the hon. Prime Minister. We have no objection that you are giving funds to Chennai. But we have received only Rs. 300 crores out of Rs. 6,000 crores we demanded. Through the Chair, I want to appeal to the Central Government to release funds regarding this disaster.

Then, discontinue compensation based on number of lives lost. When Cyclone Komen hit Bengal, 2.14 lakh people were able to take shelter in three thousand relief camps across the 12 affected districts. ...(*Interruptions*)...

DR. K. P. RAMALINGAM (Tamil Nadu): Don't compare this with Chennai. ...(*Interruptions*)...

MS. DOLA SEN: And avail help through 633 medical camps which had been set up. ...(*Interruptions*)...

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Sir, Chennai need not be referred to. ..(*Interruptions*)..

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Ms. Sen, as they have requested, do not compare. ...(*Interruptions*)... She is a new Member. ...(*Interruptions*)...

MS. DOLA SEN: Okay, Sir; I am not comparing. I am with the Chennai disaster. I feel for them and I do appreciate the Central funds towards them. I have no objection.

THE VICE-CHAIRAMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Now, your time is over. Because you are a new Member, I am allowing you one minute more.

MS. DOLA SEN: Thank you, Sir.

It is unfair to base the amount of compensation on the number of lives lost, as States which have taken pre-emptive measures will see reduced number of deaths.

[Ms. Dola Sen]

This, in turn, leads to lesser compensation paid by the Central Government while it does not take into account the amount spent by the State Government in taking the pre-emptive measures. There is no incentive to State Government from being proactive and take necessary steps to minimize loss of life or damage to land before the disaster strikes.

Allocation of SDRF from 2015-2020 -- for Maharashtra, the amount allotted is ₹ 8,195 crores; for Madhya Pradesh, it is ₹ 4,847 crores; for Rajasthan, it is ₹ 6,094 crores; and for West Bengal, it is only ₹ 2,853 crores. Thank you, Sir.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Sir, I thank our hon. Chief Minister, Amma, for making me to stand before this august gathering to place a few facts before this House because this House is very, very important for Tamil Nadu. Tamil Nadu has received unprecedented and extremely heavy rainfall. This fact is well known to everybody. Sir, Tamil Nadu has suffered a lot. These facts have been brought out by the electronic media, social media and the Press. I would like to place before this august House that but for the effective and timely steps taken by the hon. Chief Minister, Amma, Tamil Nadu would have suffered still more. Sir, I may be permitted to place a few facts before the august House regarding the steps taken by the hon. Chief Minister, Amma. The State Government has opened over 7,150 relief camps; provided food to over 19.63 lakh affected persons and also distributed over 1.35 crore food packets in affected areas. Further, to mitigate the sufferings and hardships faced by the affected people, the State Government is extending a relief package to the affected families, which includes rice, besides other material as per the State Disaster Response Fund norms. Many steps have been taken. Even ex-gratia payments have been made by the hon. Chief Minister, Amma, to the family members of the deceased and other affected persons. Our hon. Chief Minister, Amma, had initially demanded a sum of ₹ 8,481 crores. Then there was another spell of unprecedented rain in Chennai, Thiruvallur, Cuddalore, Chengalpattu, Kancheepuram and Thoothukudi. All these places are very much affected. Now, fresh assessment is going on. Hon. Amma has also written to the hon. Prime Minister that a supplementary memorandum would be submitted regarding the relief amount. Further, I would like to draw the kind attention of the House to the fact that hon. Chief Minister, Amma, has written a letter to the hon. Prime Minister on 9.12.2015. She has made four suggestions to the Central Government. Sir, I may be permitted to quote the four suggestions.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Mr. Navaneethkrishnan, just a minute. If you want to quote the letter, as per the rules,

you require the permission of the Chair. You will have to show that letter to him and then you can quote from that letter. You can only mention the date.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Okay, Sir. The four suggestions are: (a) The Insurance companies may be directed to take up the survey and settlement of the claims on a campaign mode, following a summary procedure, and with a liberal application of the norms so that such households could receive insurance payments early which would enable them to restart their normal lives. It would be desirable if this procedure is outlined at the earliest and the process of settlement of claims completed within a period of a week or ten days; (b) As a special measure, I suggest that the banks may be directed to provide a limited moratorium on repayment, as well as a rescheduling of the loans, which would lower the equated monthly instalment payments and offer a measure of relief to the flood-affected households; (c) As a special case, all such flood affected familes may be liberally extended soft loans by the banks for purchase of vehicles, educational loans to continue to fund the education of children, and personal loans of an amount up to ₹ 5 lakhs to finance essential domestic durable assets. It is only with such a package of assistance that many of these families would be in a position to restart their lives. Since many of these households would also be Jan Dhan account holders, the limits on the total eligible loan limit may be appropriately relaxed for such account holders. The Government of Tamil Nadu will provide special certification to all such families, based on which banks may be asked to expeditiously sanction the loans as per their norms. (d) For white goods and kitchen equipment to be sold in the flood affected Districts, excise duty exemption may be provided till 31.3.2016 and another three demands have been placed by the hon. Chief Minister Amma because in Chennai more than 50,000 families have been affected.

(HON. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*)

They have to be given accommodation and those 50,000 families lived along the city's waterways, namely, Adyar, Cooum and Buckingham Canal and, who have lost their homes to provide alternative housing, hon. Chief Minister Amma has demanded a sum of ₹ 5,000 crores as a special package. So, the fund may be provided as early as possible and regarding the rice and kerosene, hon. Amma has demanded from the Ministry of Food and Consumer Affairs to make a special allotment of 30000 MT of rice to Tamil Nadu at BPL rates and further from the Ministry of Petroleum and Natural Gas to allot 19,100 KL of kerosene to Tamil Nadu in addition to the regular allotment for issue under the Public Distribution system. And further she has demanded a sum of ₹ 2,000 crores and she has written to the Prime Minister and very soon a supplementary memorandum claiming the relief amount will be submitted by the hon. Chief Minister Amma. Yesterday, our hon. Finance Minister also visited

[Shri A. Navaneethakrishnan]

Chennai and met the hon. Chief Minister Amma. Previously, our hon. Prime Minister also visited Chennai and met the hon. Chief Minister Amma. Our request is that mere visit is not sufficient. You must deliver the goods. So, Tamil Nadu is well in need of your help. Please plead and I also humbly request all our hon. Members to release funds from their Member of Parliament Local Area Development Funds to Tamil Nadu as early as possible.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Already, some Members have contributed.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Already, our hon. Deputy Chairman has released ₹ 1 crore.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, I have already contributed.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN : I thank him.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I would request all Members to contribute.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI): Every BJP Member have contributed ₹ 10000/- Lok Sabha and Rajya Sabha both for the Chennai.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN : And, also our Members of Parliament, as per the direction of the Chief Minister Amma, have given one month salary as donation to the relief work. And, also I came to know that our hon. Members Shri T. K. Rangarajan and hon. Member D. Raja have released their amount from their MPLADS funds.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: They have already given it.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN : Already they have given. So, the necessary steps taken by the hon. Chief Minister Amma must be appreciated. The flood situation should not be used for politics and also for their narrow gains or political gains. So, I thank the hon. Deputy Chairman. The hon. Deputy Chairman has already made the appeal to all the Members to release their respective funds, from their MPLADS funds. I again request all the Members to immediately release the funds to see that Tamil Nadu people are saved from the sufferings. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, thank you, Mr. Navaneethakrishnanji. Navaneethakrishnanji, Tamil Nadu has the full support of all the Members of this House. I am telling you that. You can be rest assured of that. We will all be contributing. Thank you.

SHRI AMBETH RAJAN (Uttar Pradesh): Hon. Chairman, Sir, I wish to draw the attention of the hon. House as well as the Minister to two different incidents. On November 25th, a Central Team visited Chennai to assess the floods in Tamil Nadu. They visited Chennai, Cuddalore, Kancheepuram, Puducherry, Thiruvallur and many places. I think they did not go to Thoothukudi. Thoothukudi is also a worst affected district. On December 3rd and 4th, a Central Team from the Agriculture Ministry visited Odisha to assess the drought areas. These two incidents happened in a gap of a week. So, we have to ask questions to ourselves as to why this is happening. Sir, proper strategy has to be adopted by the Governments, both Central and State, to prevent such things in future. Regarding floods, Puducherry and Cuddalore are frequently affected in one way or the other. In 2013, it was Phailin cyclone. In 2015, it was unprecedented North-East monsoon rain in some coastal districts in Tamil Nadu. Even now, a part of capital city, Chennai, is under water. Like this, many places have not recovered fully. The Central Team also visited Tamil Nadu and surveyed many places. We would like to know what steps are being taken and what suggestions are being made by the survey team and what the outcomes of these visits are.

Now, I come to rehabilitation works. Medical facilities are priorities, we must know. Roads are to be repaired on a war-footing basis. Many people, particularly those living near and along the water coasts, were worst affected. They have to be provided with alternative *pakka* houses so that in future they also do not face the same problem. I request Government to extend all support to flood-affected Tamil Nadu and release sufficient funds immediately as demanded by the Chief Minister of Tamil Nadu.

Sir, in Uttar Pradesh, around 50 districts are facing severe flood like situation. Faizabad, Jhansi, Sant Ravi Das Nagar, Lucknow, Allahabad, Mirzapur, Ballia and Ghaziabad are amongst them. People living in these districts are to be given all types of support. What relief measures is the Government going to take for these people in these districts in Uttar Pradesh?

Sir, Odisha is also facing severe droughts. I request Government to take appropriate steps immediately to mitigate the sufferings of the people.

Then about our agriculture workers, these farmers in Indian villages have been affected badly by failure of agriculture. Because of this, there they commit suicide. So, I request Government to take special care and provide special package to these farmers to stop these suicides. There should be proper and permanent remedies for this.

Sir, with these words, I would like to associate myself with my colleague, Mr. Navaneethakrishnan regarding funds to be given to Tamil Nadu from the

[Shri Ambeth Rajan]

MPLADS Funds. Already our National President Km. Mayawatiji has told our MPs to help the State of Tamil Nadu by all means. With these words, I would like to conclude. Thank you.

SHRI T. K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, we are discussing on a very important subject, namely, droughts and floods. Today, while we are discussing it here, nine States are facing droughts. These States are Karnataka, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Uttar Pradesh, Telangana and Andhra Pradesh...

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (West Bengal): You have excluded West Bengal.

SHRI T. K. RANGARAJAN: Yes, even West Bengal. Sir, senior colleague, Shri Sharad Pawar, is here. He is an expert on this subject and he can deal with things effectively. But what I want to say is that drought has created misery to farmers. The suicide rate is increasing day-by-day. The Central Government of the day should find a permanent solution for these happenings. One, linking of rivers is a must, right from the rivers of the North, say, Ganga and Yamuna, and the rivers of Odisha and Andhra Pradesh up to river Cauvery. Unless you link the rivers, you cannot solve the problem permanently.

Sir, now, I come to the Chennai problem. The recent flood situation in Chennai and the surrounding areas, according to experts, has happened after 100 years. We do not know how much of the population and how many people had been affected in the earlier floods. But today, the rains have affected Chennai, Kancheepuram, Thiruvallur, Cuddalore, Puducherry and Thootukudi. I have not seen such a disaster in my lifetime. It is one of the worst floods that the State has ever faced. Of course, the Prime Minister visited there. The Chief Minister went around the area by a helicopter. And, our Finance Minister was there yesterday. Our Small Scale, Medium and Heavy Industries Minister has also visited there. I do not know what report they are going to give to the Government. So, a survey has been conducted by the Central Government officials. As correctly pointed out by Shri Ambeth Rajan, I suggest to the hon. Minister to kindly place the Report, which they have got from these officials, on the Table of the House. Sir, when the floods happened, the Army went there. But, according to the newspapers, The Hindu, The Indian Express and The Times of India, there was no coordination between the Army and the State officials. In such a situation, how can we expect that distribution of relief materials would have happened properly? There was no coordination. It is not my view. This had appeared in all the leading newspapers. Why was there no coordination? What was the arrangement between the Centre and the State? After all, it is your friendly Government. People are

suffering. They are a part of India. Sir, I would like to point out here that thousands of acres of land have perished. It is going to be very difficult to renew them. In 2013 also, Cuddalore and Puducherry were affected. Every five years, Cuddalore is affected by floods. The Government is not prepared to put up check dams. Whether it had been the DMK Government or the present AIADMK Government, consecutive Governments have not prepared the State for the floods. And people are the real sufferers. Sir, we do not know how many people have died. Some mentioned that the number is 300 and some mentioned the number as 500. There have been deaths of patients in hospitals because of want of oxygen. So, I would suggest here that the State Government should instruct the Election Commission to take up electoral rolls in these districts, visit every house and check if the list is okay. If he is missing, then, find out whether he is dead or he has gone elsewhere. Almost all the factories, small scale industries in Guindy, Ambattur, IT industry, automobile industry, were spoilt. Children did not have school for more than one month. We have never undergone such a tragedy. Sir, relief has come from everywhere. How much relief is the State Government giving? Our hon. AIADMK Leader has informed here about the relief. Our Party, DMK party, every party has started releasing the money collected from workers.

Over and above, I would like to mention that from Kerala, our Party collected ₹ 2 crores. From Bengal, Odisha, Andhra Pradesh and from everywhere our Party Members collected and deposited money to our Party. It is something great. The Indian people, ordinary people, some people from United States and Great Britain, are sending a lot of help through their NGOs. Sir, this is not enough because this is going to be a permanent thing. I would like to demand that there must be a judicial inquiry into what has happened. For example, I can tell you one thing. This Chembarambakkam Eri is the main villain. On one Tuesday, rain poured like anything and authorities were forced to discharge water at the rate of 20,000 cubic feet per second. This affected everything. Sir, BBC had already informed that there is going to be floods, it is going to rain. It is not a new thing. Everybody knows. My question is, the State Government is not prepared to face this.

SHRIMATI SASIKALA PUSHPA (Tamil Nadu): Sir, he is politicising the matter. ...(*Interruptions*)... Sir, he is politicising the matter. ...(*Interruptions*)...

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Sir, no, no; without any. ...(*Interruptions*)....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. That is only his view. Why do you worry?

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: This is not the place to say that. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Navaneethakrishnan, that is only his view. Why do you worry? That is only his view. You say the correct thing. Sit down. Why do you worry about that?

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Sir, this is not correct.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; you said that; it is on record. Now, sit down.

SHRI T. K. RANGARAJAN: Let me complete. ...(*Interruptions*)... Let me complete. What is this? ...(*Interruptions*)... Sir, you must allow me to speak. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Navaneethakrishnan, take your seat. Shri Rangarajan, please continue.

SHRI T. K. RANGARAJAN: Sir, I am not discussing anything. I demanded an inquiry on that. Today the Minister has replied to one question.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, every Member has the liberty to express his view. If anyone has got a contradictory view, they can express it only during their turn. ..(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It's okay. You need not say that.

SHRI T. K. RANGARAJAN: Sir, today in this House we didn't have the Question Hour, but one question was replied to by none other than Shri Prakash Javadekar. Shri Prakash Javadekar says, 'you fight with the Government'.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Sir, that cannot be relied upon.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Why do you worry?

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Sir, it is totally * ...(*Interruptions*)... It is totally *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Navaneethakrishnan, we are all with Tamil Nadu in this hour of crisis. So, be patient. Sit down. ...(*Interruptions*)... Shri Navaneethakrishnan, listen to me. We are all with you, with Tamil Nadu, in this hour of crisis. His party itself has contributed ₹ 2 crores. We are all with you. Let him speak. I will allow you to reply in the end. It is only his view...(*Interruptions*)... Why do you worry? ...(*Interruptions*)... It is only his view ...(*Interruptions*)... That is only his view ...(*Interruptions*)... See, that is only his view. ...(*Interruptions*)... Why do you worry? You have given the correct position ...(*Interruptions*)... That is on record ...(*Interruptions*)... That is enough...(*Interruptions*)... Sit down ...(*Interruptions*)... What do you say is on record ...(*Interruptions*)...

* Expunged as ordered by the Chair.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Sir, our hon. Chief Minister has given a detailed reply ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is not yielding ...(*Interruptions*)...

SHRI T. K. RANGARAJAN: Sir, I am not yielding ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Rangarajan has not yielded. ...(*Interruptions*)...

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: By following the agreement to release the water from Chembarambakam ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Navaneethakrishnan, don't be so impatient... (*Interruptions*)...Okay. Sit down. Sit down. Mr. Rangarajan, you continue... (*Interruptions*)...

SHRI T. K. RANGARAJAN: Sir, now, I wanted to tell our hon. AIADMK leader...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, you conclude, please. ...(*Interruptions*)...

SHRI T. K. RANGARAJAN: He demanded ₹ 5,000 crores. I want that even if it is ₹ 50,000 crores, the Central Government should release it to Tamil Nadu.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, very good. That is enough. ...(*Interruptions*)... Now, you conclude...(*Interruptions*)...

SHRI T. K. RANGARAJAN: Sir, I will conclude ...(*Interruptions*)... Sir, again and again, the problem of Chennai will come because successive Governments have not planned properly. This House must know that in 1968 ₹ 1.9 crores was given to repair Cooum.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Oh my God! You have taken five minutes extra... (*Interruptions*)...

SHRI T. K. RANGARAJAN: Sir, they have taken one minute out of that... (*Interruptions*)... Sir, in 1987, ₹ 194 crores were given. Sir, so far, for Cooum and Buckingham Adyar more than ₹ 20,000 crores spent. Experts from Singapore came. But, if rain or floods come, Chennai is drowned.

Finally, why am I saying is this? Today, the hon. Minister, Shri Prakash Javadekar, replied, 'As per some reports, the rain and excess water released at the Chembarambakam Dam resulted in the flood of Adyar ...(*Interruptions*)... So, that is why I demand an enquiry.

Thank you very much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Bhupinder Singh. ...(*Interruptions*)... Why do you worry? ...(*Interruptions*)...

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Sir, it is totally wrong; it is not correct... (*Interruptions*)... It is unfair ...(*Interruptions*)... No, no. ...(*Interruptions*)...It is not correct...(*Interruptions*)... Sir, the reply is given by the hon. Minister...(*Interruptions*)... That is relied upon by my learned senior colleague ...(*Interruptions*)... I must be given an opportunity to say that the reply given by the hon. Minister is totally incorrect ...(*Interruptions*)... It is not correct. It is unacceptable ...(*Interruptions*)...It is against the truth ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. That is enough ...(*Interruptions*)... You can send a notice ...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): Sir,...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. Bhupinder Singh. ...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, through you, I want to appeal to Mr. Navaneethakrishnan and to the AIADMK friends that if you have any dispute with the hon. Minister, you please settle. If there is anything wrong in that, you give a proper notice. If we think that you are right, we will support you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can give notice...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY: But, you allow my colleague to continue to say what he wants to say ...(*Interruptions*)...

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Sir, he is saying incorrect things. ...(*Interruptions*)...His facts are wrong ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is over...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY: No, no. I came rushing in because you are obstructing him ...(*Interruptions*)...

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: No, no ...(*Interruptions*)... He should not present wrong facts...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY: No, no. But, I came rushing in because you are disturbing him ...(*Interruptions*)... I came to rescue him. ...(*Interruptions*)...

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: No, no. He is a respected Member ...(*Interruptions*)... But, he has come with incorrect facts. ...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, please, listen me. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. That is over. ...(*Interruptions*)...Yechuryji, his speech is over...(*Interruptions*)...

5.00 P.M.

SHRI SITARAM YECHURY: Please, listen. He is reading out what the hon. Minister has said in the House ...(*Interruptions*)... Sir, please be very clear in the House ...(*Interruptions*)... Sir, our colleague, Mr. Rangarajan, was repeating what the hon. Minister said in the House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is clear. It is on record.

SHRI SITARAM YECHURY: So, don't charge him ...(*Interruptions*)...

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: It was written reply which is incorrect. ...(*Interruptions*)... I am not charging him ...(*Interruptions*)... I request him to be factual ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, Mr. Bhupinder Singh. ...(*Interruptions*)... Sit down. That is over. Mr. Navaneethakrishnan, if the hon. Minister has misled the House, there is rule for that. You invoke that rule. That is all.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, what I suggest is this. He should give a notice saying that the hon. Minister made a wrong statement.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If it is so.

SHRI SITARAM YECHURY: You please admit it today...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If he gives so.

SHRI SITARM YECHURY: ...and examine it. You must do it today.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If notice is given, I will examine it. Okay. Now, Shri Bhupinder Singh ...(*Interruptions*)... Please, go to your seats ...(*Interruptions*)... Nothing else will go on record. ...(*Interruptions*)... Shri Bhupinder Singh, please start your speech.

श्री भूपिंदर सिंह (ओडिशा)ः डिप्टी चेयरमैन सर, आप जानते हैं, कि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है। श्री के. सी. त्यागी, श्रीमती रजनी पटेल और मैंने इस चर्चा के लिए नोटिस दिया था। सर, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यह एक नारा ही रह गया है। It has become a slogan. This was my Special Mention the other day, in the last week. India is a *krishi pradhaan* country. It sounds a mere slogan but nothing in reality. आज अगर इस देश में कोई सबसे ज्यादा दुखी है, तो वह किसान है।

सर, आज यहां drought के बारे में चर्चा हो रही है। ओडिशा एक calamity prone स्टेट है। वहां drought होता है, वहां flood होता है, वहां cyclone होता है, वहां tornado होता है और वहां lightning में लोग मरते हैं। आप जानते हैं ओडिशा प्रान्त natural calamity से भरा हुआ प्रान्त है। हमारे देश् के, जैसा त्यागी जी ने कहा, 320 जिलों में severe drought हुआ है। उनकी बात

[श्री भूपिंदर सिंह]

को मैं repeat नहीं करना चाहता हूं। मेरे प्रदेश के 30 जिलों में से 25 में severe drought है। प्रदेश के 20,484 गांव इससे प्रभावित हुए हैं, डेढ़ करोड़ से ज्यादा किसान अफेक्टेड हैं, 8,82,720 हैक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है और क्रॉप damage 6,31,494 हैक्टेयर भूमि में है। इस प्रकार 70.64 प्रतिशत से भी ज्यादा वहां फसल का नुकसान हुआ है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात जो यहां से सेंट्रल टीम गई थी, उसका कहना है। उस टीम का कहना है कि 80 प्रतिशत से भी ज्यादा भूमि में खड़ी फसल का नुकसान ओडिशा प्रदेश में हुआ है।

महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी ने बार बार प्रधान मंत्री जी को चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई मदद नहीं दी गई। महोदय, यह विडम्बना है कि केंद्र सरकार से राहत नहीं मिल रही है। मुख्य मंत्री जी ने प्रधान मंत्री को दिनांक 20.11.2015 और 21.11.2015 को एक-एक चिट्ठी लिखी और फाइनेंस मिनिस्टर, श्री अरुण जेटली जी को भी चिट्ठी लिखी थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। प्रदेश से लोक सभी और राज्य सभा के सभी सांसद, पिछले वीरवार को माननीय प्रधान मंत्री जी से भी मिले, चर्चा की और इस बारे में उन्हें भी अवगत कराया, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे यहां 'फाइलिन' के कारण जो फ्लड आया था, उसके अभी तक 399.81 करोड़ यानी almost 400 करोड़ रूपए आज तक नहीं मिले, जो कि वर्ष 2013 में मिलने चाहिए थे। मैंने यह मामला यहां बार बार उठाया, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह हालत है।

सर, तमिलनाडु के लिए भी मैंने यहां निवेदन किया था कि इसे भारत सरकार National Calamity declare क्यों नहीं कर रही है। इसी प्रकार जब ओडिशा में 1999 में प्राकृतिक आपदा आई थी, तब आपने उसे भी National Calamity declare नहीं किया था। तब NDA की की सरकार थी और अहमदाबाद में जो दुखद घटना घटी, एक मिनट नहीं लगा और कहा गया कि यह National Calamity है। मैं उसकी राजनीति में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी ऐसी घटना के National Calamity घोषित होते ही, सारे भारत के Income Tax Payers ने 1 परसेंट इन्कम टैक्स वहां के लिए दिया था। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि तमिलनाडु, पुडुचेरी या आंध्र प्रदेश के लिए क्या किया गया है? मैं चाहता हूं कि इस बारे में मंत्री जी की ओर से एक definite reply यानी specific reply आना चाहिए।

महोदय, ओडिशा में जो आपकी टीम जा रही है, मैं पूछना चाहता हूं, कि वह टीम वहां की स्थिति की रिपोर्ट देने में कितना समय लेगी और कितनी मीटिंग्स होंगी? मेरा निवेदन है कि किसान के इस मुद्दे को आप वॉरफुटिंग पर लीजिए। इसे आप मीटिंग के बाद मीटिंग, कभी हाइपावर कमेटी की मीटिंग, फिर कभी कोई और मीटिंग और कभी इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग आदि कब तक चलता रहेगा? इससे किसान दुखी है। आज किसान रो रहा है। आज किसान क्यों रो रहा है, क्योंकि उसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल पाया।

महोदय, हमारे यहां हमारे माननीय मुख्य मंत्री, श्री नवीन पटनायक जी ने मनरेगा में 52 रुपए प्रतिदिन मजदूरी में बढ़ाए हैं। हमने प्रधान मंत्री जी को लिख कर दिया है कि मनरेगा में आप जो हमारे drought-affected areas हैं— कालाहांडी, बोलांगीर, नोआपाड़ा और बरगर का पदमपुर सब डिवीजन है तथा ये जो सब क्षेत्र हैं, जहां पर आज 200 ब्लॉक्स में drought की situation है, वहां के लिए हमने निवेदन किया है कि वहां immediately राहत पहुंचाने के लिए सहायता प्रदान करें। The labour is paid ₹ 174. But in our State, the Chief Minister

added ₹ 52 more. We are paying a labourer ₹ 200 to ₹ 226 per day.

सर, तेल की कीमत बढ़ी, बीज की कीमत बढ़ी, लेबर की कीमत बढ़ी, किसान की बुआई की कीमत बढ़ी, लेकिन किसान का minimum support price नहीं बढ़ा। यह सबसे ज्यादा खेद की बात है। सर, हम में क्या कमजोरी है, इस पार्लियामेंट में क्या कमजोरी है, इस देश की सरकार में क्या कमजोरी है कि हम किसान को अच्छा एमएसपी नहीं दे पाते? सर, मैंने बार बार कहा है कि अगर किसान हंसता है तो देश हंसेगा और किसान रोएगा तो देश को रोना पड़ेगा। सर, ओडिशा से लेकर बंगाल से लेकर, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र बुंदेलखंड से लेकर जो practically identified areas है, मंत्री जी, आज कम-से-कम हमें यह तो बताइए कि क्या आपके पास रिपोर्ट है कि भारत के कौन-कौन से जिले most drought affected जिले हैं? सर, अभी यहां Water Resource Minister बैठी थीं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको हमारे यहां के medium, major projects के बारे में लिखा है और उनके लिए मांग की है। सर, पिछले साल में कुल 19 करोड़ 88 लाख रूपए मिले और इस साल 1051 करोड़ की सीडब्ल्यूसी की क्लिअरेंस होते हुए भी हमें हमारे major, medium projects के लिए रूपयों की आवश्यकता है। इसीलिए मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज अगर...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

श्री भूपिंदर सिंहः सर, सरकार अच्छे दिन लाना चाहता है, तो हम सब आपके साथ हैं, लेकिन अच्छे दिन उसी दिन आएंगे, जिस रोज किसान के घर अच्छी पैदावार होगी, किसान की treasury में पैसा होगा, किसान जिस दिन मजबूत होगा, उस रोज भारत निर्माण होगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

श्री भूपिंदर सिंहः नहीं तो इस देश के अच्छे दिन कभी भी नहीं आ सकते। अगर इस बारे में किसी की दो राय है, तो हम उस पर चर्चा करते के लिए तैयार हैं। आप इस सदन में उस पर चर्चा कीजिए। Lastly, Sir, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मंत्री महोदय cooperative federalism की बात पर हमें बहुत दुख हो रहा है। आपने अक्टूबर में ओडिशा में जो कमेटी भेजी, हम लोगों ने नहीं कहा था कि आप कमेटी भेजिए। आपने एक कमेटी अक्टूबर में भेजी, उसके बाद जब हमने लिखकर दिया तब दूसरी कमेटी भेजी। तो यह दूसरी कमेटी क्या करने गयी थी और पहली कमेटी ने क्या किया? आप यह स्टेट के ऊपर मत थोपिए। सर, lastly, ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is your second 'last'.

श्री भूपिंदर सिंहः सर, मैं आज सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मेरा price rise के बारे में एक नोटिस था।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. वह कल है।

श्री भूपिंदर सिंहः सर मेरे जिले में, कालाहांडी में आडिशा में सारे स्टेट में कोई भी कॉटन का सपोर्ट प्राइस लेने के लिए तैयार नहीं है। सर, आज चाइना और दूसरे देशों को जो इम्पोर्ट होता था, वह बंद हो गया है। सर, आज हमें market facilities के बारे में यहां मंत्री जी से जवाब मिले कि किसान जो पैदा करता है, उसे market facilities कौन देगा? सर, अमेरिका 2,50,000 रुपए अपने किसान को minimim subsidy देगा और हमें डब्ल्यूटीओ में कहा जाएगा कि आप एक पैसा नहीं दे सकते। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is all. Now, please conclude. Take your seat.

श्री भूपिंदर सिंहः आप किसी के सामने मत झुकिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Take your seat.

श्री भूपिंदर सिंहः आपके साथ सारा देश है। आप डब्ल्यूटीओ के सामने सीधी बात कीजिए कि हम अपने किसानों को सब्सिडी देंगे और जितनी जरूरत है, देंगे। Thank you, Sir.

श्री शरद पवारः सर, एक गंभीर विषय के बारे में हम तकरीबन 2 घंटे से चर्चा कर रहे हैं। जहां तक मेरी information है, देश के 10 राज्यों में 227 जिले सूखाग्रस्त हैं। देश में सूखे की स्थिति हो और उसके लिए उपाय करने की बात हो, तो भारत सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन संविधान के माध्यम से कृषि का विषय ऐसा है जिसमें स्टेट की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। ऐसे समय में स्टेट गवर्नमेंट्स को इस पर ध्यान देना होगा। स्टेट गवर्नमेंट्स को भारत सरकार को लिखना होग, उन जिलों के नाम बताने होंगे, कितना क्षेत्र खराब हुआ है, कितनी फसल खराब हुई है, इसकी पूरी-पूरी information देनी पड़ेगी। उसके बाद इसमें सच्चाई और गम्भीरता कितनी है, यह देखने के लिए भारत सरकार को वहां टीम भेजनी पड़ेगी। इसके आधार पर भारत सरकार अंतिम निर्णय ले सकती है। आज 10 राज्यों की यह समस्या है और जिन राज्य सरकारों ने सूखा डिक्लेयर किया है, ऐसे 227 जिलों की इंफॉर्मेशन शायद भारत सरकार के पास आई होगी। इससे ज्यादा होगी तो मुझे मालूम नहीं है, मंत्री जी इसमें फंक्शनल लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। सूखे की परिस्थिति से किसानों का कितना नुकसान होता है, यह तो बताने की जरूरत नहीं है। इस सदन का हर सदस्य किसानों की समस्या को जानता है। जब उनको किसी संकट का सामना करने की नौबत आती है, तब उनको कितनी कीमत देनी पड़ती है, इसकी जानकारी भी सदन के सभी सदस्यों को है। इसलिए मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ चार-पांच सुझाव देना चाहता हूं, जिन पर भारत सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। एक—हमने और इस सदन के सभी सदस्यों ने इससे पहले 'मनरेगा' को समर्थन देने का निर्णय ले लिया था। महाराष्ट्र जैसे राज्य में कई सालों से 'इम्प्लॉइमेंट गारंटी स्कीम' थी और कर्णाटक में इस तरह की एक अलग स्कीम थी। कई और राज्यों ने अलग अलग ऐसी सकीमें बनाई थीं। भारत सरकार ने डा. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में एक नई दिशा देश को दी, सभी राज्यों को दी और 'मनरेगा' के अधीन गांव में काम करने का इंतजाम, मजदूरों को रोज़ी देने का इंतजाम इस सदन ने अपनी सम्मति देकर पूरा किया। भारत सरकार ने इस पर अमल करना शुरू किया और आज की हुकूमत भी इस पर ध्यान दे रही है। 'मनरेगा' में क्या क्या काम लेते हैं? इसमें कहीं सड़कें बनाते हैं, कहीं नहरें बनाते हैं और कहीं सड़क के साइड में plantation करते हैं। इस तरह के कई अच्छे काम इसके तहत होते हैं। मुझे लगता है कि अभी ऐसा समय आया है कि किसान की खेती में काम करने के लिए क्या हम 'मनरेगा' का मजदूर दे सकते हैं, इस पर ध्यान देने की आावश्यकता है। चाहे उसके क्षेत्र में कुआं खोदने का काम करना हो, पानी की नहर बनानी हो, फसल में इंटर कल्टिवेशन करने का काम हो, इन सभी कामों को करने के लिए हम वहां 'मनरेगा' का मजदूर दे सकते हैं। हम इस बारे में सोच सकते हैं कि इसमें कुछ हिस्सा या 25 per cent तक हिस्सा किसान भी उठा सकता है। इससे भारत सरकार का बोझ कम हो जाएगा और यह बात पक्की हो जाएगी कि मान लीजिए किसी किसान के खेत में दस मजदूरों को भेजा गया, तो वह किसान इस पर ध्यान देगा कि सुबह से शाम तक काम होता है या नहीं,

इसका कोई अच्छा रिजल्ट मिलता है या नहीं। आज हम देखते हैं कि कई जगहों पर 'मनरेगा' का काम चालू है। उसमें पचास लोग आते हैं और पांच सौ लोगों का हिसाब लगाते हैं, हम वहां पैसा लगाते हैं। हम कई बातें देखते हैं मगर जब खेती के क्षेत्र के काम का और किसान के खेत में काम का, किसान की सहमति से काम का, उसके सुपरविज़न से काम का हम बंदोबस्त करेंगे, इंतजाम करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि ज्यादा काम होने की संभावना है। इतनी बड़ी रकम भारत सरकार अगर इस काम के लिए, इस योजना के लिए देती है, तो इसका फायदा अच्छी तरह से हो सकता है, इस बारे में बात करने और सोचने की आवश्यकता है।

दूसरी बात यह है कि मैंने खुद मराठवाड़ा के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर वहां की परिस्थिति का जायज़ा लिया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि मेरे ही राज्य में यवतमाल नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है और वहां सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं। मैंने एक महीना पहले दो दिनों तक वहां के आत्महत्याग्रस्त गांव में घर-घर जाकर लोगों से बात की और उनके परिवारों से बात की और जाना कि क्यों इस प्रकार की परिस्थिति पैदा होती है। यवतमाल एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र में खेती के क्षेत्र में परिवर्तन करने वाला एक नेता, जिसका नाम वसन्त राव नायक है, वह वहां से आता था। किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। उनके जिले में यह जो परिस्थिति पैदा हो रही है, यह क्यों हो रही है? मैंने वहां जाकर देखा, मराठवाड़ा में जाकर देखा और कुछ जिले हैं, जहां यह समस्या होती है, वहां गांव-गांव में जाकर देखा। इसमें दो-तीन बातें सामने आईं। एक, फसल खत्म हो गई, फिर सोसायटी से या बैंक से पैसे लिए थे, बीज लाए, बुवाई करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, वह मेहनत की, खर्च किया, लेकिन जिस तरह से बारिश की अपेक्षा करते हैं, उस तरह से बारिश नहीं आई और पूरी फसल हाथ से गई। उनके सिर पर इतना बोझ पड़ गया। एक साल, दो साल, तीन साल, तक सूखे की परिस्थिति का सामना करने के बाद वे उस बोझ का सामना नहीं कर सकते थे, इससे उनका छुटकारा नहीं हो सकता था और एक दिन उन्होंने आत्महत्या का रास्ता सीखा। हमें इसके बारे में सोचना होगा। डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में इस सम्बन्ध में तब एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था। मुझे याद है कि मेरे राज्य में वर्धा डिस्ट्रिक्ट है, यह महात्मा गांधी जी का डिस्ट्रिक्ट है और गांधी जी के डिस्ट्रिक्ट में आत्महत्या की संख्या ज्यादा हो गई। उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम वहां जाकर देखना चाहते हैं। हम दोनों ही वहां गए, किसानों से बात की। एक ही बात सबके सामने आई, सभी साथियों के माध्यम से हमने यह सुना कि उनके सिर पर यह जो बोझ हो गया है, चाहे बैंक का हो, चाहे प्राइवेट साहूकारों का हो, चाहे सोसायटी का हो, उससे उनका छुटकारा नहीं है और इसलिए वे आत्महत्या के रास्ते पर जाते हैं। यहां आकर 5-6 दिन बैठ कर, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, अन्य मिनिस्ट्रीज़ हों, सभी को विश्वास में लेकर वहां एक जबर्दस्त कदम उठाने की कोशिश की गई। डा. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में किसानों को 70 हजार करोड़ रूपए की माफी देने के लिए, उनको राहत देने के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया। हमने देखा कि अगले 2-3 साल में आत्महत्या का रेट कम हुआ था, मगर आज फिर वह आत्महत्या का रेट बढ़ रहा है। किसी सरकार के लिए हमेशा इस तरह से माफी देना इतना आसान नहीं है, मैं जानता हूं, मगर हमें सोचना होगा कि उनके सिर पर यह जो बोझ है, क्या हम यह बोझ re-schedule कर सकते हैं? अगर हम माफ कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। अगर माफ नहीं कर सकते हैं, तो उनको इसे एक साल में वापस करना है, उनको 5 या 7 साल का समय दे दें। इस बार उनसे जो सूद लेने

[श्री शरद पवार]
की बात थी, उसे माफ कर दें। आगे की फसल लेने के लिए बैंक के माध्यम से या सोसायटी के माध्यम से उनको आर्थिक सहायता देने के बारे में हम वहां कुछ न कुछ तैयारी करें। क्या हम इस तरह की बात कर सकते हैं, यह बात सोचने की आावश्यकता है। अगर पूरी माफी नहीं दे सकते हैं, तो आप कम से कम इसके बारे में जरूर सोच सकते हैं कि इसको कैसे re-schedule कर सकते हैं। यह बोझ है, उसको एक साल में देने के बजाय अगर हम उनके लिए 5, 6, 7 साल का समय दे सकते हैं, तो यह बोझ कम हो सकता है। अगर नई फसल लेने के लिए उनकी और आर्थिक मदद हो सकती है, तो मुझे लगता है कि वे किसान फिर अपनी खेती करने के लिए आगे आ सकते हैं और वे आत्महत्या के रास्ते पर नहीं जा सकते हैं। इसलिए इसके बारे में ध्यान देने की आावश्यकता है।

जिन जिलों में सूखे की परिस्थिति है, वहां जाकर मैंने एक बात देखी कि पशुधन की स्थिति बड़ी गम्भीर है। दो साल पहले ऐसी स्थिति थी, मैंने खुद अपने राज्य में देखा कि वहां की सरकार ने 12 लाख से ज्यादा पशुओं का कैटल कैंप किया था और पशुधन बचाने के लिए बहुत बड़ी मदद की थी। इसमें भारत सरकार ने उनकी मदद की थी। आज कई राज्यों में वहां की स्थिति मालूम करने के बाद पता लगता है कि कई राज्यों ने पशुधन बचाने के लिए कोई खास उपाय किए हैं, ऐसी बात हमें देखने को नहीं मिलती है। अगर एक बार पशुधन खत्म हो गया, तो किसान के सामने आगे की खेती करने में मजबूरी पैदा हो जाती है और इसलिए मुझे लगता है कि पशुधन को बचाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और उसे मदद देने के लिए भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए।

उपसभापति जी, तीसरी बात, कई गांवों में मैं ने देखा है कि पीने के पानी की वहां समस्या है। लातूर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है। सदन के कई सदस्यों को शायद मालूम होगा कि लातूर से सांसद के प्रतिनिधि एक जमाने में लोक सभा के स्पीकर थे, जिनका नाम शिवराज पाटिल था। उनके डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद पता लगा कि वहां पानी कितने दिन में मिलता है? वहां बीस दिन में एक बार पानी मिलता है। किसी के घर में जाइए, तो पाएंगे कि पानी के बैरल जगह जगह पर रखें हैं, क्योंकि बीस दिन में एक दिन पानी मिलता है। पीने के पानी की यह समस्या लातूर जैसे एक महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट की है। यहां हमारी रजनी ताई बैठी हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट में कई ऐसे गांव हैं, जहां दस-दस दिन, बारह-बारह दिन तक पानी नहीं मिलता है, एक दिन पानी मिलता है। पानी के जो सोर्सेज़ हैं, वे भी ड्राई होना शुरू हुए हैं। वहां की हुकूमत मदद देने के लिए ध्यान देती है, मगर आज परिस्थिति इतनी गम्भीर बनी हुई है और इसलिए हमें इस बारे में अलग से कोई कार्यक्रम लेने की आवश्यकता है। हम जब वहां लोगों को रोजी देने की बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा ध्यान वाटर कंजर्वेशन पर होना चाहिए। इसके बारे में मदद हो, ऐसे जो काम हों, इन पर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा और इससे हमारी आगे की समस्या कैसे कम होगी, देखना होगा और इस पर हम जो कुछ कर सकते हैं, वह करने की आवश्यकता है।

यहां कई बातें कहीं गईं। मैं सदन के सामने एक बात कहना चाहता हूं कि समझो, एक फसल गई, एक साल की फसल का नुकसान हुआ, चाहे गेहूं हो, चावल हो, धान हो, ज्वार हो या बाजरा हो, इससे देश का नुकसान होता है, किसान का नुकसान होता है, मगर बागवानी की फसल का जब नुकसान होता है तो इससे ज्यादा गम्भीर नुकसान होता है। हॉर्टिकल्चर में

एक फसल लगाने के लिए, फल लगाने के लिए चार-चार, पांच-पांच साल राह देखनी पड़ती है, मगर एक बार हॉर्टिकल्चर का काम होने के बाद इसका फायदा आगे कई साल, बीस साल, पंद्रह साल, पचास साल तक मिल सकता है, चाहे आम की बागवानी हो, चाहे अंगूर की बागवानी हो, चाहे सेब की बागवानी हो, चाहे अमरूद की बागवानी हो, चाहे सीताफल की बागवानी हो। दूसरी फसल और बागवानी की फसल में बहुत अंतर है। एक बार अगर बागवानी की फसल गई, तो फिर किसान उठ नहीं सकता। उसे उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मुझे याद है, दो-साल पहले जब ऐसी परिस्थिति पैदा हुई थी, तब भारत सरकार ने बागवानी को बचाने के लिए 35 हजार रूपए प्रति हेक्टेयर खाली पानी देने के लिए यहां से हर राज्य को दिए थे और इसका फायदा लेकर कई राज्यों ने अपनी बागवानी की फसल को बचाने का काम किया था। मुझे लगता है कि आज भी ऐसा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अपने देश में इस क्षेत्र में किसानों ने बहुत बड़ा काम किया है। शायद हमारे बहुत से साथियों को यह मालूम नहीं होगा कि आज दुनिया में horticulture and vegetable production में भारत का हिस्सा दूसरे नंबर पर है। यह भारत के किसानों ने जो मेहनत की, उससे हम यहां तक पहुंचे हैं, तो उनकी बागवानी को बचाने के लिए हम लोगों को एक अलग तरह से मदद करने की आवश्यकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी मदद करने के बारे में भारत सरकार सोचे और इस मामले में राज्य सरकार की जो डिमांड होगी, उसमें उनको मदद करे।

आखिरी बात मुझे यह कहनी है कि जब-जब ऐसी समस्या आती है, तो फसलों के ऊपर बहुत बुरा असर होता है। इसलिए भारत सरकार ने छह साल पहले दो इंस्टीट्यूट बनाए। फसल पर कई तरह से असर होता है, जैसे कभी पानी नहीं मिलता तो असर होता है, कहीं ज्यादा पानी आ गया, तो उसका असर होता है। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं—Biotic and abiotic stress on crops. और इस बारे में संशोधन की आवश्यकता है और किसानों को हम किस तरह से सलाह दे सकते हैं, इसके लिए भारत सरकार ने दो इंस्टीट्यूट बनाने काम किया—एक रांची के पास और एक पुणे के पास। ये दोनों इंस्टीट्यूट खड़े हुए। सैकड़ों एकड़ जमीन वहां की सरकार ने उन्हें दे दी, मगर आज वहां जाने के बाद यह पता लगता है कि वहां जो साइंटिस्ट्स अपॉइंट करने हैं और इस क्षेत्र में जो संशोधन, रिसर्च चालू होकर किसानों को अच्छी तरह से सलाह देने का काम होना चाहिए, वह काम करने के लिए वहां साइंटिस्ट्स की वेकेसीज़ अभी तक भरी नहीं हैं और इसलिए वहां का काम जिस तरह से होना चाहिए, वह हो नहीं रहा, क्योंकि वह काम सूखाग्रस्त किसानों को मदद करने वाला काम है और इस बारे में कुछ न कुछ कदम मंत्री जी जल्दी उठाएंगे, इतना मैं विश्वास करता हूं।

महोदय, एक और बात मुझे कहनी है। कई राज्यों के बारे में हमेशा एक बात आती है कि जो पानी खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें बड़ा हिस्सा, गन्ने की फसल के लिए जाता है। महाराष्ट्र में ऐसी शिकायत है, वेस्टर्न यू.पी. के बारे में ऐसी शिकायत है, नॉर्थ कर्णाटक के बारे में ऐसी शिकायत है। कई राज्य ऐसे हैं जहां चीनी का उत्पादन ज्यादा होता है, वहां गन्ने की फसल को पानी ज्यादा देते हैं, इस तरह की शिकायत आती है। मुझे लगता है कि हमें इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। मैंने देखा कि इण्डोनेशिया में वहां की सरकार ने, वहां के कृषि विभाग ने इस क्षेत्र में अलग काम किया है। उन्होंने गन्ने की एक अलग वेराइटी तैयार की जिसमें ड्राउट रेजिस्टेंट कैरेक्टर है। 50 दिन पानी नहीं दिया तो भी वह गन्ना बच सकता है। पढ़ने के बाद हमने एक टीम भेजी, एक शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसका मैं अध्यक्ष हूं। वसंतदादा

[श्री शरद पवार]

पाटिल नाम के हमारे राज्य के बड़े नेता थे और खेती और सहकारी के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान था। इनके नाम पर यह इंस्टीट्यूशन है, जहां 120 से ज्यादा साइंटिस्ट्स काम करते हैं। उस इंस्टीट्यूट की टीम मैंने वहां भेजी, इसकी रिपोर्ट मेरे पास आ गई है और फोटो भी आ गए हैं। उन्होंने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड शुगरकेन वेराइटी डेवलप की, जी.एम. वेराइटी, जिसको पानी की आवश्यकता बहुत कम है। आज इस तरह से काम यहां भी हो सकता है। आज दुनिया में चीनी का उत्पादन करने वाला और एक्सपोर्ट करने वाला भारत आज दूसरे नम्बर का देश है। ऐसी परिस्थिति में इतने बड़े गन्ने की फसल और पानी के इस्तेमाल का इससे कोई रास्ता निकल सकता है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। मगर आज डिपार्टमेंट ऑफ बॉयोटेक्नॉलोजी का व्यू बदलना चाहिए। जी. एम. क्रॉम के बारे में मालूम नहीं कि नई सरकार की नीति क्या है। दुनिया में कई देशों ने इसका लाभ लिया है। आज हम खाद्य तेल आयात करते हैं। जहां से खाद्य तेल आयात करते हैं, वहां का जो खाद्य तेल या ऑयल सीड का जो उत्पादन होता है, वह जेनिटिकली मॉडिफाइड सिस्टम से ही होता है, यानी बाहर से हम इंपोर्ट करके यहां खाते हैं लेकिन अपने यहां हम किसानों को यह करने की इजाजत नहीं देते, ऐसी स्थिति यहां पैदा हुई है। और इसलिए रिसर्च के बारे में, साइंस के बारे में हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। जहां तक सूखे की परिस्थिति का सामना करने वाली कोई नई फसल डेवलप करने की बात हो, जिस रास्ते हम वह कर सकते हैं, उस रास्ते काम करने का मौका हमें साइंटिफिक कम्युनिटी को हमेशा देना चाहिए। इतना मैं कहता हूं और आपसे इजाज़त लेता हूं।

SHRIMATI B. JAYASHREE (Nominated) : Namaskaram, Sir. सर, मैं अपना भाषण कन्नड़ भाषा में देना चाहती हूं। मैं इसके लिए आपसे इजाज़त चाहती हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Okay.

SHRIMATI B. JAYASHREE: Thank you, Sir.

(Hon. Member spoke in Kannada)

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE) *in the Chair.*]

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, where is the translation?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): She did not inform.

SHRIMATI B. JAYASHREE : No, no, I informed, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE): If you informed just now, it will not be possible.

SHRIMATI B. JAYASHREE : No, no.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE) : When did you inform?

SHRIMATI B. JAYASHREE : In the morning.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE): If you can speak in English, it will be a little better and we are trying to get the Translator. We are trying to get it done. If you can, it will be very nice.

SHRIMATI B. JAYASHREE : I have already given notice.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE) : Yes, but, the information is not there and it was not done. I am trying to get it done.

SHRI TIRUCHI SIVA : What happened? She had already informed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE) : If she has already informed, then why didn't the Translator come. Okay, carry on, please.

SHRIMATI B. JAYASHREE : Sir, I try to speak in Hindi.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE): I am trying to find out.

SHRI SHARAD PAWAR : She can speak in her language.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE) : That is what I am saying.

SHRI SHARAD PAWAR : And then circulate her speech in English and Hindi to all Members.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE) : Okay, good suggestion.

SHRIMATI B. JAYASHREE : Should I?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE) : We do not have a system like that but I think we should do it. Please carry on. Can you speak in English?

SHRIMATI B. JAYASHREE : No, because in the morning I came to know that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE) : You speak such good English. You can try it.

SHRIMATI B. JAYASHREE : But, still, because it is a feeling from my heart. I cannot put fully in another language.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE) : Okay, please carry on. Please carry on or can I call somebody else and then I can call you back.

SHRIMATI B. JAYASHREE : Sure.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE) : It will be better. Please sit down. Thank you. अब ये translator organise करें।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर): सर, मैंने यह चर्चा सुनी और दो बिन्दुओं के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। जैसा अभी शरद पवार जी ने कहा कि हमें रिसर्च को छोड़ना नहीं चाहिए, रिसर्च को आगे ले जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जीएम के बारे में इस सरकार की भूमिका क्या है? हमारी भूमिका बिल्कुल साफ है कि विज्ञान को हम रोक नहीं सकते, रोकना नहीं चाहते, इसको और आगे ले जाएंगे और इसलिए जीएम के भी ट्रायल्स, जो पूरी सेफ्टी के साथ होते हैं, उन ट्रायल्स के लिए हम परमिशन दे रहे हैं। लेकिन शरद पवार जी, इसमें एक मदद आपको भी करनी पड़ेगी या सभी राज्यों को करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी no State is allowing free trial. There is a catch-22 situation. हमारी कमेटी सेफ्टी के रूल्स के साथ ट्रायल के लिए परमिशन दे रही है, लेकिन कोई भी राज्य अगर ट्रायल करने के लिए परमिशन नहीं देगा, तो क्या होगा? मैं एक विस्तृत चर्चा के लिए आपके सामने ...**(व्यवधान)**...

SHRI DEREK O'BRIEN : Sir, let us get the name of Minister right.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE) : Yes, it will be changed. Do not disturb please.

श्री प्रकाश जावडेकर: सर, इस संबंध में मुझे एक ही बात कहनी है कि इसके लिए एक तो राज्यों से परमिशन नहीं मिलती, यह एक दिक्कत आ रही है। अब फेडरलिज्म के ज़माने में फिर केंद्र सरकार पावर अपने हाथ में ले, यह भी संभव नहीं होता, लेकिन फिर विज्ञान का रथ आगे कैसे जाएगा? किसानों को नई तकनीक चाहिए। मैं मानता हूं कि किसानों को नई तकनीक की जरूरत है और अगर हम परमिशन नहीं देंगे, तो क्या होगा? जैसे आपने कहा कि आज जो विदेश से हम तेल ला रहे हैं, वह तेल जीएम है, वह तो हम खा ही रहे हैं, तो विदेश से लाकर कैसे क्या होता है? मुझे एक बात और कहनी है, वह यह है कि बंगलादेश में जीएम को परमिशन मिली है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI TIRUCHI SIVA: You believe in 'Make in India'. Just because we are importing, it is not a compulsion that we should also get the same here.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR : No, I am just telling one view. I respect all views. That is the first democratic condition that I am following. The issue is कि बंगलादेश में जीएम आ गया। अब बंगलादेश से असम के लोग ला रहे हैं? फिर पश्चिमी बंगाल में आएगा, फिर बिहार में आएगा, फिर सारे देश में आएगा। Is it the right way? मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूं कि हमें देश की वैज्ञानिक तरक्की रोकनी नहीं चाहिए। ह्यूमन सेफ्टी का पूरा एंगल ध्यान में रखकर भी तरक्की करनी है, तो हमें विज्ञान और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी और यह प्रोडक्टिविटी की ही लड़ाई है। जैसा शरद पवार जी ने कहा कि drought resistance नई variety है, तो हम ऐसे गुण क्यों नहीं लाएंगे? लड़ाई क्या है? हमारे देश में दुनिया की

17 फीसदी कैटल आबादी है। We have 17 per cent cattle population of the world. We have only 2.5 per cent of the land and only 4 per cent fresh rain water resources. How are we going to meet the demands of the growing population and its growing protein needs? That is also an issue. Therefore, I appreciate the feeling, but I appreciate the other view also. Let me also talk about floods in Tamil Nadu. Today, there was a question which could not be taken up because in our House Question Hour is always a casualty. ...(*Interruptions*)... Sir, we are doing politics in everything. Today, one question was whether the climate change has caused floods in Tamil Nadu. ...(*Interruptions*)...

श्रीमती रेणुका चौधरी (आंध्र प्रदेश)ः आप सब्जेक्ट के ऊपर रहिए। **...(व्यवधान)...**

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: I am on the issue of floods and climate change, which has been raised. ...(*Interruptions*)... I am on a point. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE): He is not giving answer to the question. Let him speak. He is not giving answer to the question.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Whether climate change impacts floods and droughts, is also an issue. Let me tell you that yes, climate change increases the frequency of floods and droughts. But a particular drought or a particular flood cannot be attributed to that. That is the scientific position as of today. Now what is the issue? You say that there are many other factors responsible for floods.

SHRI DIGVIJAYA SINGH (Madhya Pradesh): Sir, I am on a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE): Under which rule?

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, firstly the hon. Minister is not speaking from his seat. The second point of order is that the hon. Minister should not be replying to the subject. This subject belongs to the hon. Minister of Agriculture. What is his intervention for? ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE): Let him intervene. ...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: This is not his subject, Sir. ...(*Interruptions*)... The hon. Minister is here. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE): He is not replying. He is not replying. There is no point of order.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, he is taking away the fundamental rights of the Members of Parliament. ...(*Interruptions*)...

श्री प्रकाश जावडेकरः सर, क्लाइमेट चेंज और जीएम क्रॉप मेरा मंत्रालय देख रहा है, इसलिए मैं उतना ही बता रहा हूं। ...**(व्यवधान)**... I am not trespassing. मेरे views भी होते हैं, लेकिन views के अलावा जो इसमें है, वह मैं बता रहा हूं। मेरा आज भी एक उत्तर था। ...**(व्यवधान)**... चेन्नई में फ्लड कैसे आया? उसमें एक उदाहरण आया। उसके चार-पांच कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। Let me make it clear कि जैसे वहां इतनी torrential rain गिरी, यानी वह नैचुरल कैलामिटी थी, that is one fact. The second fact, उसकी जो resilience building शहर में होनी चाहिए, वह प्लानिंग न होने के कारण, एंक्रोचमेंट के कारण सभी नाले and all natural drains are closed. That is not the case of Chennai alone.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE): How much more time will you take, Mr. Minister?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, two minutes. This is not the case of Chennai alone. It has happened in all the cities. What is happening is, in Uttarakhand, people are doing construction in the riverbed. That is the problem. Then in Kashmir, all the natural drains were blocked. These things increase the intensity of natural disasters. That is the point I wanted to make.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I am on a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): Under which rule?

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, under Rule 358.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): Mr. Tiruchi Siva, under which rule, are you raising your point of order?

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, Rule No. 358. Let me first submit my point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE): Under which rule? ...(*Interruptions*)...

SHRI TIRUCHI SIVA: Okay, I don't mind. That rule must be adopted for everyone. Sir, Shri T.K. Rangarajan was referring to the reply which the hon. Environment Minister,...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE): There is no Rule No. 358; sorry.

SHRI TIRUCHI SIVA: I can raise any point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE): You can't just say anything and start speaking. ...(*Interruptions*)...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I can raise any point of issue. ...(*Interruptions*)... I have a very relevant issue. Kindly permit me. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE): You cannot just get up and start speaking.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I am sorry; it is Rule 258. Without having the Book, I am saying it. When Shri. T.K. Rangarajan was referring to the reply which was tabled this morning by the hon. Environment Minister ...(*Interruptions*)... Just a moment I am coming to your help. Shri Navaneethakrishnan, when interrupted him, said that the Minister's reply was *. * is an unparliamentry word, Sir. You kindly look into that and expunge it. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): Okay, I will give a ruling then. ...(*Interruptions*)... Now, Shrimati Jayashree, ...(*Interruptions*)... Please don't disturb her. ...(*Interruptions*)... Now, the interpreter is there. You may speak. ...(*Interruptions*)... I will get back to you ...(*Interruptions*)... I will get back to you. ...(*Interruptions*)... Please don't disturb the lady. She has got up ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)...

श्रीमती बी. जयश्रीः** नमस्कार, मैं तुमकूर के गुब्बी तालुक से आती हूं। इसलिए मैं यही की स्थिति के बारे में बोलूंगी। इसका मतलब यह नहीं है कि देश के अन्य भागों की स्थिति ठीक है। सच तो ये है कि देश भर के किसानों की स्थिति भी गंभीर है।

इस जिला के ९ तालुक हैं और सभी तालुकों में रागी, मूंगफली और नारियल की खेती होती है। मूलतः ये सारी फसल बारिश पर आधारित है। समय पर बारिश नहीं होने पर किसान दुःखी हो जाते हैं, क्योंकि वहां के लोग सिर्फ खेती करना जानते हैं और कृषि के लिए बारिश ही मूल आवश्यकता है।

बारिश न आने पर किसान कंगाल होकर डर जाता है फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश में कर्ज में डूब जाता है। वह सोचता है "चलो इस बार बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ, अगली बार बारिश होगी"। इसी आशावादी प्रवृत्ति की वजह से कर्ज लेकर अपनी खेती करता है। जब लगातार कई सालों तक बारिश नहीं होती है तो किसान की मदद करने के लिए कोई नहीं होता, और वह असहाय हो जाता है।

किसान देश का बहुत मुख्य अंग है। किसान की खेती से खाद्यान्न पैदा होने से ही देश सुखी रह सकता है। अगर किसान नहीं हो तो देश उन्नति करने के बदले मर जायेगा। किसान अपनी खेती के लिए बैंक के अलावा निजी लेन देन करने वालों से भी कर्ज लेते हैं जिनका ब्याज बहुत होता है। जब कर्ज का बोझ बहुत हो जाता है तब कर्जदारों का प्रभाव और किसान का अपमान बढ़ जाता है और किसान आत्महत्या कर लेते हैं। इसी तरह हर गांव में आत्महत्या का कहर बढ़ जाता है तो पूरा कृषक समाज कर्ज में डूब जाता है और इसका असर देश के ऊपर बहुत बुरा पड़ता है। अगर किसान आत्महत्या करते हैं तो उस परिवार की मुखिया की मृत्यु हो जाती है। इससे एक परिवार खत्म हो जाता है। इसका बुरा प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है।

---

*Expunged as ordered by the Chair.

**Hindi translation of the orginal speech made in Kannada.

[श्रीमती बी. जयश्री]

जब किसान देश को अन्न देगा तभी देश सुखी रह सकेगा। देश की जनता देश को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर देश की तरक्की कर सकते हैं। मगर यदि किसान नहीं रहेंगे तो देश का ही अंत हो जाएगा। मैं किसी भी सरकार की तरफ उंगली नहीं दिखा रही हूं। हम आजकल आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मगर आधुनिकीकरण के नाम पर पर्यावरण, जमीन, पहाड़ आदि का विनाश कर रहें हैं। इसका परिणाम मौसम पर विपरीत पड़ रहा है।

हमें प्रौद्योगिकी भी चाहिए। मगर प्रौद्योगिकी सर्वत्र नहीं होनी चाहिए, आखिर बड़े से बड़े यंत्र को शुरू से अंत तक चलाने के लिए कोई एक व्यक्ति चाहिए। उस व्यक्ति को खाना किसान देता है, मगर आज हमने उस किसान के हाथ से काम ही छीन लिया है। उसका हाथ खाली है, हम सबने उस किसान को मार डाला है।

जब भी किसान आत्महत्या कर लेते हैं तब हम उसकी मौत के कारण ढूंढने की बजाय उसके परिवार को मुआवजा देकर चुप हो जाते हैं। किसान अपनी जिन्दगी भर हमें अन्न देता है मगर हम उनकी जिंदगी को 5-10 लाख रूपये देकर तोल देते हैं। किसान की जिन्दगी को पैसे से तोलना कहां तक ठीक है। हमें किसान को काम देने की दिशा में सोचना है। वैश्चिक तापमान को नियंत्रण करने की दिशा में सोचना है।

महोदय, मैं इन शब्दों को किसी को खुश करने के लिए नहीं बोल रही हूं। मैं अपने हृदय से विनती करती हूं कि हम सब मिलकर उस किसान को जो देश के लिए अपने जीवन का बलिदान देते हैं, बचाना है।

धन्यवाद, शरणु शरणार्थी।

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, just now, we heard Shri Sharad Pawar, one of the competent authorities on Indian agriculture, speaking on the subject. He made a very eloquent speech. It is true that our country is very diverse. In several parts, we are witnessing very serious drought, and in some places, say, Tamil Nadu, Puducherry and some parts of Andhra Pradesh, we have been witnessing extremes in rainfall and floods. Why is this happening? The time has come when we should understand the dialectics of nature. The dialectics of nature says that there should be a balance between people, land, water and air. Whenever the balance is disturbed, we have to face the fury of nature. That is what we have been witnessing today. This Government, the present Government, can claim one achievement, and that is, the dismantling of the Planning Commission and instituting the NITI Aayog. Now, the NITI Aayog has got all Chief Ministers as its members. This Government speaks about co-operative federalism. Mr. Minister, if you believe in co-operative federalism, you must take all the States into confidence. You must consult all Chief Ministers. You must evolve a comprehensive National Policy on land use. That is number one. Then, you must evolve a comprehensive National Water Policy; that is, how to link rivers and how to share river waters. You should arrive at certain solutions to the problems. Even after the intervention of the Judiciary, the river

water problems have not been solved. When I say this, Sir, what is the problem in Tamil Nadu? There are some systemic problems. It is not to blame this party or that party. There are systemic problems. If there are problems in the States, then, yes, we will take up those problems with the State Governments and fight it out there. But here, in Parliament, in the august House, we should discuss as to what is happening to our water bodies, rivers, canals, forests and mountains. They are disappearing. They are being allowed to be encroached upon. Successive Governments have failed to stop this encroachment. Let us speak with conscience and honesty. Let us stretch our conscience and admit that successive Governments have failed to stop this encroachment. Now, how to manage this country? Shri Sharad Pawar said that we should continue our research. Yes, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act is one of the significant Acts this Parliament enacted, but, at the same time, there are irregularities. We will have to fight the irregularities. This Act must be implemented. This scheme should be streamlined, strengthened and implemented to help the poor, landless agricultural workers, primarily, and the *Dalits* and *Adivasis* in the different parts of the country. But there is a controversy of whether we will have to go for Genetically Modified crops (GM crops) or organic crops. And there are reports in Tamil Nadu emanating even during this extreme rains and floods that organic crops could withstand whereas other crops failed. What to do with this? So, the Parliament should think of certain larger issues and it is not a short-term issue now that we are fighting against each other. How can we conserve our own natural wealth, our own water sources, our own land, conservation of land, conservation of water? What are we thinking? What is the job of your NITI Aayog? I am asking you. What is NITI Aayog going to do? You will have to think over this.

Coming to concrete issues, Tamil Nadu, Puducherry and some parts of Andhra Pradesh are badly affected and they need assistance from the Centre. ...(*Time-bell rings*)... You are giving, but did you agree to these States? Are they enough to meet the requirements? The State Government has asked for much more and the Centre should admit. And, moreover, I would like to ask you -- the Prime Minister made some announcement, the Finance Minister made some announcement, you also can make some announcement -- Is it really done? I am asking you: Is it really done? Has money been sent? Has it been cleared? You tell the Parliament because we will have to tell our people also. So announcement alone cannot be enough. Tamil Nadu and Puducherry need more Central assistance without any further delay and Centre should ensure this.

Coming to the last issue, Sir, agriculture is in deep crisis. You are also, I understand, one of the senior persons who have keen knowledge in agriculture and

[Shri D. Raja]

Shri Sharad Pawar is sitting here. Agriculture is in deep crisis and farmers are passing through unprecedented distress and they are committing suicide. What is the root cause for this? It is indebtedness, farmer's indebtedness. This indebtedness drives them to suicide. Why do farmers get into debt trap? Agriculture has become non-remunerative. They do not get remunerative prices and my Comrade, my beloved colleague Tyagiji, was talking about MSP and the paddy producers do not get reasonable price. Sugarcane producers do not get reasonable price. So, remunerative price is not given to the farmers. Agricultural workers do not get adequate wages. How to face these problems? Yes, there is drought and Government should take up measures on a war-footing on floods and rains and Government should come out with positive thinking and a positive measures. Here, the short-term measure is immediate financial assistance to the States, and for longterm measures, you will have to think of a comprehensive water policy, a comprehensive land use policy; otherwise, this country cannot progress. Sharad Pawarji was talking about horticulture and other developments in the country. Yes, India is progressing. ...(*Time-bell rings*)... India is one of the major developing countries and we can claim that we are the most developed among developing countries, but we are failures and we need a comprehensive outlook to protect our agriculture and to change our agriculture. But corporatisation of agriculture will not be helpful. Co-operative agriculture and protection of small and marginal farmers must be one of the priorities of our Government. Sir, agriculture must be given the priority. And, in fact, Parliament should have some special Session to discuss Indian agriculture and problems faced by Indian agriculture.

Thank you very much.

श्रीमती रजनी पाटिल (महाराष्ट्र)ः सर, बाढ़ या अकाल की वजह से जो आपदा पैदा होती है, उसके उपर Short Duration Discussion के तहत आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए प्रथमतः मैं आपका आभार मानती हूं।

सर, मैं एक किसान परिवार से आती हूं। यहां पर जिस-जिस क्षेत्र का नाम लिया गया, उस मराठवाड़ा क्षेत्र और बीड, जहां पूरे देश में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं, मैं उस constituency से आती हूं। हम बचपन में सुनते थे, मराठी में खेती को शेती बोलते हैं, कि उत्तम शेती, यानी जो बहुत अच्छा काम है, यानी उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, यानी जो व्यापार करने वाले हैं, वे मध्यम लोग हैं और कनिष्ठ नौकरी, यानी नौकरी करने वाले लोग कनिष्ठ हैं। लेकिन आज इतने सालों के अनुभव से मुझे यह लगने लगा है कि सबसे कनिष्ठ शेती है। आज शेती कनिष्ठतम हो गई है, मध्यम नौकरी हो गई है और उत्तम व्यापार हो गया है। व्यापारियों के दिन बहुत अच्छे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे दिन आए हैं। इसलिए अभी यहां उलटा क्रम लगना शुरू हो गया है।

मराठवाड़ा क्षेत्र में एक भयावह परिस्थिति पैदा हुई है, वहां लगातार 4 साल से अकाल पड़ा है। वहां 4 साल से बारिश नहीं हुई है, वहां बारिश का पानी नहीं है। इससे पहले हमारे यहां 1972 में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। उस समय हम बहुत छोटे थे और तब हमने देखा था, सुना था कि बहुत सारे लोग माइग्रेट करके पुणे, मुम्बई, पिम्परी छिंछोड़ में आए थे। जो एरियाज़ हमारी सिटीज़ में है, वहां पर आए थे। लेकिन आज यह परिस्थिति है कि खाने की तो छोड़ो, पानी पीकर जीने की नौबत आ चुकी है। जिसे हम मराठवाड़ा बोलते हैं, अब हम उसको टैंकरवाड़ा बोलेंगे, इस तरह से परिस्थिति पैदा हो गई है। वहां टैंकरों से ही पानी दिया जाता है। सर, statistics यह कहता है कि हमारे मराठवाड़ा क्षेत्र में, हमारे बीड डिस्ट्रिक्ट में हर 35 घंटे में एक आत्महत्या हो रही है, हर डेढ़ दिन में एक आत्महत्या हो रही है। हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि पहले हम इसकी चर्चा करते थे, अब हमने वह चर्चा भी पीछे छोड़ दी है। हमें लगता है कि ऐसा ही होता रहेगा। इस स्थिति से मुझे ऐसा लगता है, डरावनी स्थिति यह है कि हमारी संवेदनशीलता का नष्ट होना, यह मुझे सबसे ज्यादा खतरे की चीज़ लगती है।

सर, हमारे यहां जमीन के नीचे एक-एक हजार फीट तक बोरवेल ले जाएंगे, तो भी पानी नहीं आएगा। हमारे यहां 4-4 साल से, जैसा मैंने बताया कि कुछ भी उपज नहीं है। रबी तो छोड़ो, वह तो बहुत कम आती है, लेकिन खरीफ का भी जो अनाज होता है, वह भी हमारे यहां नहीं आता है। बीच में हमारे यहां औरंगाबाद क्षेत्र में एक चोरी हो गई। जब उस चोरी के लिए पुलिस उस महिला को पकड़ने के लिए गई, तो उसने कहा कि मैंने इसलिए चोरी की, क्योंकि मेरे बच्चे भूखे थे और इसलिए मैंने रोटी चुराई। यह गांव में आज की परिस्थिति है। हम यहां पर चर्चा अलग करते हैं, लेकिन वहां की परिस्थिति बहुत अलग है।

सर, मैं यहां खुद अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताना चाहूंगी कि जो बीड डिस्ट्रिक्ट है, वहां हर साल 3 लाख से अधिक लोग माइग्रेट होते हैं। वे गन्ना तोड़ने के लिए जाते है। कोई कर्णाटक जाता है, कोई गोवा जाता है, कोई वेस्टर्न महाराष्ट्र जाता है। वे गन्ना तोड़ने का काम करते हैं। वे लोग दीवाली के समय अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपनी भेड़-बकरियों को साथ लेकर 6 महीने के लिए माइग्रेट हो जाते हैं और गन्ना तोड़ने का काम करते हैं। वे गन्ना तोड़कर अपना पेट भरने को काम करते हैं। वे सब marginal farmers हैं, बहुत छोटे-छोटे किसान हैं। उनके लिए हमने क्या सोचा है, यह भी सोचा है, यह भी सोचने की बहुत आवश्यकता है।

सर, गन्ना हो, कपास हो, सोयाबीन हो, धान हो, उनका MSP भी निश्चित करने की आवश्यकता है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): Just one minute. It is 6 o' clock. I think, it was decided that we will continue beyond 6 o' clock. So, we have the sense of the House.

श्रीमती रजनी पाटिलः यहां स्वामीनाथन कमिटी के बारे में जो बात की गई, मुझे लगता है कि उसको सही मायने में लागू करने की आवश्यकता है।

सर, जो यूपीए की सरकार थी, उस सरकार में जब सोनिया जी के निर्देश पर मनमोहन सिंह जी और पवार साहब ने महात्मा गांधी नरेगा स्कीम declare कर दी, तो उसके माध्यम से हमारे हजारों किसानों को, मजदूरों को फायदा हो गया था। ...**(व्यवधान)**...

6.00 P.M.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI GHULAM NABI AZAD): Sir, reply can be tomorrow.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, it can be tomorrow.

SHRI D. RAJA: Reply can be tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE): Okay.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*)

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, we can complete it today...(*Interruptions*)...

DR. K. P. RAMALINGAM: Sir, reply should be completed today...(*Interruptions*)... Sir, today itself we will complete the debate. ...(*Interruptions*)...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, tomorrow we may not get time. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): Sir, it should be completed today.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is the response of the Government?

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः सर, पहले से जो एक-दो नाम आए हुए हैं, **...(व्यवधान)...** जो एक-दो नाम पहले के हैं, उनको इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दे दिया जाए। उसके बाद ऑनरेबल मिनिस्टर रिप्लाई करें। जो पहले से नाम हैं, बाद में भी कुछ नाम आए होंगे, हमें लगता है कि अगर उनको एकोमोडेट करेंगे, तो फिर बड़ा लंबा चलेगा।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, whoever wants to speak should be allowed. This is an important subject. ..(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I don't know what happened in my absence. But I have to say one point. Unless you finish the whole discussion today, how would you take up another subject tomorrow? According to the decision taken in the meeting of all party leaders, if you have taken up one subject today, it must be completed. There is another subject for tomorrow; I think, it is on price rise. Then, there is the third subject pending. If allowed, then there would be the fourth subject also, that is, the substantive motion. So, if all these are there, how to finish them? Unless you finish this today, you will not be able to take up those subjects. So, we fill finish it today. We will sit a little more. That is one point.

The second point is, some names...

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, everyone wants to participate because this is a very important subject. Everyone wants to speak and they would not allocate time for such an important subject. Whoever wishes to participate should be allowed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please listen. Now the time allotted is two hours and thirty minutes. We have already exceeded that. However, the subject being important, we can extend the time and discuss. I have no problem. I want to say one thing on giving the names. There is a standing instruction from Mr. Chairman, which has been accepted by all that the names should be given before the commencement of the discussion. Now I have got some names received after the commencement of the discussion. I don't know what to do about those. As a special case, the subject being that important, if the House ...(*Interruptions*)..

I will find out.

श्री मुख़्तार अब्बास नक़वीः सर, जो बाद में नाम आए हैं, उनको मिलाकर अभी 12-13 नाम और हैं। पहले से जो नाम हैं, वह शायद दो बचे हुए हैं। तो पहले से जो नाम हैं, उनको ही मौका दे दें, बाकी के जो नाम हैं उनको दूसरे किसी इश्यू पर मौका दे दें।

श्रीमती रेणुका चौधरीः हमें भी बोलना है।

श्री मुख़्तार अब्बास नक़वीः हमें कोई आपत्ति नहीं है। **...(व्यवधान)...** सर, ऐसा है कि जो बाद में नाम आए हैं, उनको मिलाकर एप्रॉक्सिमेट 12-13 नाम हैं। इसलिए बेटर है कि जो पहले से नाम हैं, उनको आप ले लें। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will do one thing. Let me dispose of the names given first, which we received on time. After that, we will decide.

श्रीमती रजनी पाटिलः सर, यूपीए की सरकार में सोनिया जी के निर्देश से और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जब शरद पवार साहब कृषि मंत्री थे और महाराष्ट्र में जो हमारे लीडर थे, उन्होंने रोजगार योजना शुरू की थी। उसी को आदर्श मानते हुए महात्मा गांधी नरेगा योजना स्वीकृत हुई और उससे बहुत सारे हमारे काश्तकारों को, हमारी लेबर्स को फायदा हो गया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए उसमें हर डिस्ट्रिक्ट ले लिया गया और उसमें सौ दिन का कार्यक्रम तय कर दिया गया। मुझे यहां पर यह कहना आवश्यक लगता है कि उसी कार्यकाल में जो खेत की उपज होती थी, उसमें साढ़े चार फीसदी की बढ़त हो गई थी। जैसा यहां पर बताया गया, यूपीए सरकार ने किसानों के लिए 70 हजार करोड़ रुपए की कर्ज मुक्ति का एक बहुत बड़ा निर्णय लेकर उनको राहत दी थी। आज बिहार के चुनाव में हमारे प्रधान मंत्री जी ने दस नहीं, बीस नहीं, तीस नहीं, एक लाख पच्चीस हजार करोड़ का पैकेज देने का ऐलान किया। मुझे लगता है कि जब वे चुनाव के टाइम पर ऐसी घोषणा करते हैं, तो देश के किसानों के आंसू पोंछने के लिए उन्हें एक अच्छा पैकेज देने की आवश्यकता है। जिन देशों का हमने कभी नाम भी नहीं सुना था, हमारे प्रधान मंत्री उन-उन देशों में जाते हैं और मन की बात कहते हैं। मुझे यह कहना आवश्यक लगता है कि हमारे मराठवाड़ा और वर्धा क्षेत्र में, जिसका अभी माननीय पवार साहब ने उल्लेख किया था, वहां माननीय मनमोहन सिंह जी खुद गए थे और वहां के किसानों से मिलने का कष्ट उठाया था, किसानों से बातचीत की थी। लेकिन आज तक भी हमारे प्रधान मंत्री जी ने यह कष्ट नहीं उठाया, वे वहां कभी नहीं गए और न ही उन्होंने पूछा कि वहां के किसानों की क्या हालत है?

[श्रीमती रजनी पाटिल]

सर, मेरे दो-तीन सुझाव हैं। हमारे महाराष्ट्र में अकाल को देखने के लिए टीम बार-बार भेजी जाती है। कृषि मंत्री जी वहां पर तीन बार आ चुके हैं। इस बार तो उनका ऐसा हाल हुआ, जैसे ही हमारे किसानों ने देखा कि सेंटर से कोई टीम आई है, उन्होंने बड़े-बड़े पत्थर लेकर उनके ऊपर फेंकने शुरू कर दिए। उन किसानों को इतना गुस्सा आया, वे बोले आप दो-तीन बार यहां पर टीम तो भेज चुके हैं, लेकिन कभी कोई मदद नहीं भेजते अथवा किसी तरह की मदद का कोई ऐलान नहीं करते। टीम वाले अधिकारियों ने स्वयं बताया कि हम सिर्फ देखने के लिए आए हैं, हम मदद नहीं करेंगे। इस तरह आप किसानों के जले के ऊपर नमक छिड़कने का जो काम करते हैं, वह काम आप मत करिए, यही मैं आपसे कहना चाहती हूं।

सर, मैं दो-तीन सुझाव देना चाहती हूं। CRC Insurance या अनाज का जो बीमा किया जाता है, उसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। किसानों से बीमे की किस्त तो ले ली जाती है, लेकिन उनको उसका पैसा नहीं मिलता है। हमें प्राइवेट साहूकारों या मनीलैंडर्स के खिलाफ कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। जैसा कि अभी बताया गया, नरेगा के अंतर्गत हमारे जो खेत हैं, उनमें छोटे-छोटे तालाब बनाए जाने की आवश्यकता है। ...**(समय की घंटी)**... किसानों के लिए solar motors दिए जाने की आवश्यकता है। अकाल हो या बारिश, सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें एक Long Term Programme बनाना चाहिए या एक कार्यबद्ध योजना बनानी चाहिए। मदद करने के लिए ऑफिसर्स तो बाद में पहुंचेंगे, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमें जब प्यास लगती है, तभी हम कुआं खोदने के लिए निकलते हैं। मुझे लगता है कि इसके लिए एक समयबद्ध प्रोग्राम बनाया जाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत सेंसिटिव विषय है। किसानों को बचाया जाना चाहिए। किसान नहीं बचेगा, तो देश नहीं बचेगा, इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूं, धन्यवाद।

DR. K. P. RAMALINGAM: Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. This is a very important subject and I would speak from my heart. Hence, I would be speaking in my language, the national language, Tamil.

*Saint Thriuvalluvar has said,

‘Who ploughing eat their food, they truly live;

The rest to others bend subservient, eating what they give’.

That is, They alone live who live by agriculture; all others lead a cringing, dependent life. That was the age of Thiruvalluvar. But today’s rulers give importance to the people who depend on others. People who are dependent on others live prosperously. But those who do ploughing and farming are suffering and they commit suicide. Why does this situation arise?

In the history of the world, in Indian peninsula, all States have suffered in one way or the other either due to flood or due to drought. Now also, nine States have

*English translation of the original speech made in Tamil.

suffered due to drought. Three States including Puducherry have suffered due to flood. Why does this situation arise? Every time we suffer from flood. Whenever there is flood, States have to seek assistance from the Centre. When there is drought, then also, States have to depend on the Centre.

All taxes are collected by the Union Government from the people. But the Union Government has to give assistance to the States. The Central monitoring team is visiting the states and is giving compensation such as ₹ 500 crore or ₹ 1000 crore etc. They are giving compensation in such a way as if they are giving alms to the people. Earlier Chhattisgarh had flood, then Uttarakhand had flood. Now Tamil Nadu and Andhra Pradesh are suffering from flood. All States are getting flood consecutively. But what are the steps taken by the Union Government to prevent floods in future? No action has been taken so far. Every year you are giving compensation. Next year also it will happen somewhere. Odisha had flood in the year 1999. The devastation is still existing. Rehabilitation activities did not take place. People are not compensated fairly. In such a situation, what is the solution?

Many of my Hon'ble colleagues mentioned that interlinking of rivers is the only solution to prevent floods. If that can not be done by the Union Government, what can be done? Can't we protect people from drought and flood? We can. Israel had 90% of desert land. But they have improved their agriculture. We have brought luxury cars and iphones. Can't we provide modernized equipments to farmers? Why is our agriculture not modernized so far?

Micro irrigation and drip irrigation are carried out successfully in the States of Maharashtra and Tamil Nadu where the Governments have given 100% subsidy to these types of irrigation. When Dr. Kalaignar was the Chief Minister of Tamil Nadu in the year 1990, he gave free electricity to farmers. Why can't such schemes be implemented in other parts of the country? Farmers are suffering in all the States of India due to flood and drought. How can we protect them? I would like to mention four important points:

First, Interlinking of rivers

Second, Proper procurement price to the farmers as per their agricultural input cost. Onion, which is cultivable in 90-92 days...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have completed your time. ...(*Interruptions*)... There are so many speakers. ...(*Interruptions*)... Take one minute more. ...(*Interruptions*)...

DR. K. P. RAMALINGAM: This farmer is under your protection, Sir. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Say the points what States did. No need of giving lecture. ...(*Interruptions*)...

DR. K. P. RAMALINGAM*: I would like to mention four important points:

First, We have to interlink rivers.

Second, proper procurement price has to be given to the farmers as per their agricultural input cost. We have to encourage the farmers to carry out farming activities and to protect agriculture.

Third, Animal Husbandry has to be improved. It helps farmers to enhance their livelihood. A new institute by name 'Indian Council of Veterinary Research' (ICVR) has to be established in the lines of 'Indian Council of Agricultural Research' (ICAR).

The fourth and the most important point is that farmers have to be given land insurance. They have to be given not only crop insurance, but also land insurance. Whenever there is flood, their land is also affected.

In four or five districts of Tamil Nadu such as Cuddalore, Thanjavur, and Thiruvallur, sand has silted over the agricultural land. Each and every farmer has to spend ₹ 5 lakhs per acre of land. Therefore, this problem also has to be considered by the Union Government.

In order to protect water bodies, we need not wait for an order from the Supreme Court. The authorities concerned have to take action to protect water bodies. Sir, Finally, we need a special budget for agriculture to protect farmers. We need an exclusive budget for agriculture as is done in the case of Railways. With these words, I conclude my speech. Thank you.

श्री उपसभापतिः श्री बलविंदर सिंह भुंडर। आपके पांच मिनट हैं। आप पांच मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए। There are some more speakers. That is why I am saying.

श्री बलविंदर सिंह भुंडर (पंजाब)ः ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं तो एक सेकंट भी वेस्ट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट अपनी बात कहूँगा। ...**(व्यवधान)**...

ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन साहब, इस समय जो देश के किसान की हालत है, वह मैं नहीं कहता, सारा हाउस कहता है और सारा देश कहता है कि इससे बुरी हालत आज तक कभी नहीं हुई। उसका कारण क्या है? एक तो उसका कारण ढूँढ़ना चाहिए और दूसरा, फिर करना क्या चाहिए, ये दो प्वाइंट्स हैं। हम बहस करते हैं और बहस करके चले जाते हैं। जो भी बोलता है, किसान के पक्ष में बोलता है, लेकिन किसान की बात कभी नहीं मानी गयी। किसान की जो कमोडिटीज़ हैं, उनका प्राइस अनाउंस किया जाता है। लेकिन परचेज़ सिर्फ व्हीट एंड राइस, वह

*English translation of the original speech made in Tamil.

भी Punjab, Haryana and some parts of other States, not whole of the country. ऐसा करके जब प्राइस एनाउंस किया जाता है तो वह प्राइस भी सफिशिएंट नहीं होता। वह भी बहुत मिनिमम, मिनिमम तो लफ़्ज़ ही है लेकिन मिनिमम से भी मिनिमम है। मैं फिगर में नहीं कहना चाहता, क्योंकि फिगर आपके पास है, गवर्नमेंट के पास है। पहले किसान सुसाइड करने को बुजदिली समझता था, लेकिन आज हिन्दुस्तान का नहीं, वर्ल्ड का जो सर्वे है, वह कह रहा है कि दो मिनट में एक किसान इंडिया में खुदकुशी कर रहा है। वह पंजाब जो "किंग ऑफ एग्रीकल्चर" था, पंजाब का किसान भी अब इस स्थिति में आ गया है। कारण क्या है? उसका इंपुट्स प्राइस तो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो उनका सपोर्ट प्राइस है वह डे बाई डे कंट्रोल किया जाता है, ताकि उसका प्राइस ज्यादा inflate न करे। मैं हैरान हूं कि कंज्यूमर कैसे बचेगा, अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा? यह कौन सा फॉमूर्ला है? फॉरेन के किसान को कितना पैसा दिया जा रहा है? वहां से ऑयल सीड, वेजिटेबल ऑयल मंगा रहे हैं, वहां से पल्सेज कितनी मंगा रहे हैं और कितना पैसा जा रहा है? कंट्री में कितना वेस्ट हो रहा है। हिन्दुस्तान में एक साल में जो wheat rot हो रहा है, जहां उसको insecticides damage कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की एक साल की टोटल क्रॉप के बराबर हमारा एक साल का डैमेज है। हमारा इतना ही फ्रूट्स में डैमेज है, इतना ही वेजिटेबल्स में डैमेज है। जब वेजिटेबल्स का प्राइस बढ़ जाता है तो हम बेबस हैं। कहते हैं कि अब तो शॉर्ट हो गया। शॉर्ट कब हुआ, जब गरीब किसान के खेत से क्रॉप आ गया। अब आप कहते हैं आलू दो रुपए प्रति किलोग्राम है; ओनियन भी दो रुपए प्रति किलोग्राम है। ओनियन भी ऐसा ही है, लेकिन जब वह किसान के यहां से चला जाएगा तो वही सौ रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। आजादी को 67 साल हो गए। क्या देश का किसान ऐसे ही रुलता रहेगा? हम कहते हैं कि असली किसान है, इसलिए मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं न मैं इनको ब्लेम देना चाहता हूं और न मैं उनको ब्लेम देना चाहता हूं। ब्लेम से क्या होगा? कितनी देर से हम यह कर रहे हैं। मेरे इधर भी दोस्त बैठे हैं जिन्होंने ज्यादा समय राज किया है, अब ये हमारे साथी हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कभी किसी ने सोचा है कि जो Minimum Support Price है, स्वामीनाथन का जो फॉमूर्ला था, वह हमारे मेनिफेस्टो में भी है, बी.जे.पी. के मेनिफेस्टो में भी है। मेरा ख्याल है कि जो मेरे दोस्त बोल रहे हैं, वह एक्जांपल उनका दे रहे हैं। 2004 में जो कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट शायद 2008 में आई थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसकी रिपोर्ट डस्टबिन में चली गई। किसी ने सोचा ही नहीं। वह तो कहता था कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे 50 परसेंट ज्यादा दें, लेकिन मेरा ख्याल है कि 50 परसेंट कम दिया जा रहा है। और कम भी देकर नहीं, फिर कोई भी परचेज़ नहीं कर रहा, ऐसा कैसे होगा? जो 1120 बासमती था, जिसको एक्सपोर्ट करते थे, उसका प्राइस एक हजार रुपए प्रति क्विंटल है, जो पीछे पांच हजार रुपए प्रति क्विंटल था। आज से सात साल पहले कॉटन का प्राइस था छः हजार रुपए प्रति क्विंटल, अब चार हजार रुपए प्रति क्विंटल है और क्रॉप की yield भी down आ गई है। इंफ्लेशन कितना हाई है, prices three times up चले गए, जो इनपुट्स के हैं। इसलिए किसान क्या करे? फिर सुइसाइड के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। किसान कभी कर्ज़दारी से नहीं दबना चाहता, वह शर्म से मर जाता था। अब कहते हैं कि किसान कर्जा नहीं दे रहा है, वह तो लोन का डिफॉल्टर है। आज इण्डस्ट्री के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए इतना जतन किया जा रहा है कि उसको लैंड इतना सस्ता प्रोवाइड किया जा रहा है, टैक्स पर रिबेट दिया जा रहा है। अगर उसकी इंडस्ट्री को लॉस हो जाए तो लाखों-करोड़ों नहीं अरबों रुपया उसका माफ

[श्री बलविंदर सिंह भुंडर]

किया जाता है, लेकिन किसान बेचारे को लोन दिया जाता है 14 परसेंट पर, फिर उसके ब्याज पर ब्याज है, फिर उसकी क्रॉप per year डैमेज हो जाती है, कभी ड्राउट से हो जाती है, कभी hailstorm से हो जाती है, कभी flood से हो जाती है। इस प्रकार उसको कोई रिलीफ नहीं है, उसका कोई इंतजाम नहीं है। इसलिए हर तरफ से किसान मारा जा रहा है। मैं आपके जरिए विनती करना चाहता हूं, ज्यादा नहीं, सिर्फ चार प्वाइंट्स इसके लिए सजेस्ट कर रहा हूं। सबसे पहले हम बार-बार कहते हैं कि हम इंश्योरेंस देंगे। जो यूनिवर्सल रिसर्च, वह स्कीम हम लागू करें, प्रति किसान लागू करे, प्रति फैमिली लागू करें, यानी कि एक यूनिट है। यह नहीं कि 10 गांवों या 5 गांवों का एक यूनिट है। एक किसान के खेत में भी लॉस है, तो उसको भी दिया जाए। जो इंश्योरेंस है, उसके प्रीमियम का 50 परसेंट सरकार दे। किसान को इसके लिए गारंटी दी जाए, यह नहीं हो कि वह फिर कोर्ट में जाए कि मुझे मिल नहीं रहा है।

दूसरी मांग यह है कि जो क्रॉप लोन है, वह किसानों को तीन परसेंट सिम्पल इंटरेस्ट पर दिया जाए। तीसरी मांग यह है कि रिसर्च पर जोर दिया जाए। किसानों को सीड सस्ता दिया जाए। यह नहीं हो कि यह मल्टिनेशनल कम्पनी के हाथ में आ जाए। ऐसा नहीं हो कि सीड 2 हजार रुपए प्रति किलो या 1500 रुपए प्रति किलो हो जाए और बेचने के पहले उसको पांच रुपए भी नहीं मिलते हैं, इसलिए सीड सस्ते में प्रोवाइड किया जाए और रिसर्च करके अच्छा सीड पैदा किया जाए।

चौथी मांग यह है कि स्वामीनाथन कमिशन की जो रिपोर्ट है, अगर आप सारी सिफारिशों को लागू नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने जो तीन-चार प्वाइंट्स बोले थे, Profitability in agriculture के बारे में the report said that the cost of production was higher than the Minimum Support Price in the case of 12 crops including rice and wheat. The Commission submitted 5 reports that make suggestions for improving the agricultural sector through enhancing productivity, profitability and sustainability of the major farming systems of the country. The other crops were jowar, maize, bajra, ragi, tur, moong, urd, gram and barley. "It would be extremely unlikely that in the long run farmers would continue to cultivate those crops where the cultivation costs are not recovered," the report stated. ...(*Time-bell rings*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

श्री बलिंवदर सिंह भुंडरः सर, अगर किसान ऐसे ही पैदा करता रहा, जिससे लॉस हो, तो यह सब कुछ खत्म हो जाएगा, किसान खत्म हो जाएगा, देश का जो सिस्टम है.... इससे क्या होगा? कहीं माओवादी आ गए, कहीं और बगावत आ जाती है, suicide ही अकेली प्रॉब्लम नहीं है, देश का लॉ एण्ड ऑर्डर भी खत्म हो रहा है। उस पर भी इतना पैसा बरबाद हो रहा है, इसलिए में आपके जरिए यह कहना चाहता हूँ ...

श्री उपसभापतिः ठीक है, आपने अच्छा प्रवाइंट बताया।

श्री बलिंवदर सिंह भुंडरः सर, मैं आधे मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। सर, हम कहते हैं कि diversification पर जोर दें। इतना पैसा बरबाद हो रहा है। वह पैसा हम जो oilseeds

बाहर से मंगाते हैं, pulses बाहर से मंगाते हैं, उसके लिए दें। उसके लिए price assure करें और purchase करें। उसकी एमएसपी हाई करें। आपने एमएसपी कितनी बढ़ाई है? पहले मूंग की एमएसपी 3 हजार रुपए प्रति क्विंटल थी, अब आपने उसको 3200 रुपए प्रति क्विंटल किया है और अगर वही मूंग मार्केट में जाए, तो वह 12 हजार रुपए प्रति क्विंटल है। हम 30 रुपए या 32 रुपए प्रति किलो देते हैं, लेकिन मार्केट में यह 200 रुपए प्रति किलो या 180 रुपए प्रति किलो या 150 रुपए प्रति किलो है, इससे कम नहीं है। सर, यह कैसे चलेगा? सर, यह तो जोक है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो सही है, रिएलिटी है, उस पर सरकार आए। कुछ तो यत्न करे। अगर किसान नहीं बचेगा, तो देश नहीं बचेगा। ...**(समय की घंटी)**... सर, यह कहने की बात नहीं है, यह हम देख रहे हैं कि हमारे देश में कितनी गड़बड़ है, हर स्टेट में गड़बड़ है। उसका कारण यही गरीबी और बेरोजगारी है।

श्री उपसभापतिः आपने बहुत अच्छा बोला, कृपया अब आप बैठ जाइए।

श्री बलिंवदर सिंह भुंडरः सर, इसी कारण से गांव से लोग उठ कर शहरों में आ रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... सर, मैं आधे मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। सर, पंजाब, जिसने देश को बचाया, शास्त्री जी ने कहा था कि एक दिन मंडे को व्रत रखो, घर-घर गमले में अनाज उगाओ। यह शास्त्री जी ने नारा दिया था, आपको याद होगा, लेकिन पंजाब के किसान ने उस चैलेंज को मंजूर किया। देश का अनाज अब बाहर जाने लगा। शरद पवार जी के समय में 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपए का हमने एक्सपोर्ट किया था। अब स्थिति यह है कि पंजाब के किसान पर drought आ जाए, लेकिन हम पैदा कर देते हैं, नो रिलीफ, अगर ब्लड आ जाए, तो नो रिलीफ ...**(समय की घंटी)**... Sprinkle और drip system से वहां तो पानी ही सूखता जा रहा है। आपके यहां तो पहले ही कम है और अब हमारे यहां भी खत्म हो चला है।

श्री उपसभापतिः आपने जो बोला, उससे मैं भी सहमत हूँ।

श्री बलिंवदर सिंह भुंडरः सर, मैं आपके जरिए कहना चाहता हूँ कि किसान बचेगा, तो देश बचेगा, इसलिए पंजाब को बचाओ और देश को बचाओ ताकि देश में शांति आए और देश तरक्की करे, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, please consider those suggestions. This is what I am saying. Now, Shri Anil Desai. You have to consider those suggestions. That is what I am saying. Now, Shri Anil Desai.

SHRI ANIL DESAI (Maharashtra): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir, for giving me opportunity to speak on this very serious subject, 'situation arising due to floods and drought in the country'.

Sir, during the last few years, our country has been witnessing serious droughts or floods in different parts of different States. Obviously, climate change phenomenon has been taking its toll and devastation of life and property has also crossed its limits in recent times. Recently, we have seen in Chennai the worst of the floods, affecting Tamil Nadu, Puducherry and parts of Andhra Pradesh and Telangana.

[Shri Anil Desai]

Similarly, we have seen the effect of drought, how serious it is. Sir, being an agrarian economy, we have to depend on monsoon for our agricultural produce, but due to vagaries of nature, the results are otherwise. In the last three years or so, Maharashtra has seen worst of the droughts, particularly in the Districts of Marathwada, Paschim Vidarbha and some parts of northern Maharashtra. Sir, in parts of Marathwada, if you happen to see, as hon. Sharad Pawarji and a few Members who have spoken on Maharashtra situation have stated, the worst condition is going on there, and due to drought, there are no crops. There is scarcity of water. Drinking water has become biggest of the problems. People have to go far away. People have migrated from their Districts. Perhaps, they have gone to other States in search of water for the living purposes.

Another thing is that drought is there because of either more rainfall or scanty rainfall. On the other side, if you happen to see, unseasonal rains and the danger of hailstorm also have been witnessed in parts of Maharashtra during the last few years. The farmer has to see the ready-to-harvest getting ruined in front of his eyes, and because of this situation, he is left with no other alternative but to commit suicide. Committing suicide is not a new thing now in Maharashtra. In fact, Maharashtra is the number one State as far as number of suicides is concerned in the country. The banks which are lending the loans, or even the private money lenders, those who are lending the loans to the farmers, their economy is shattered. And despite knowing the fact that they had nothing to offer and they are in no position to repay the loan, banks or moneylenders go to the stage of coercion. This leads to a very drastic situation where farmer is left with no other alternative but to commit suicide. We have seen the cases where not only farmer but also his entire family commits suicide.

Sir, my party, Shiv Sena, under the able leadership of Uddhavji Thackeray, has taken a lead to help poor farmers of Marathwada. In that direction, we have offered them monetary help. We have gone to the extent of contributing towards farmers' share which is to be paid while accepting the Government schemes which are there, which have been given by the State of Maharashtra. So, we are doing our bit, but substantial steps are needed to be taken. Something drastically needs to be done for the people of farming community.

Sir, in Maharashtra, time and again, the Central Government has sent its teams. Even after their assessment, which is entangled in redtapism, the reports have not yet been submitted or they are on the way of being submitted to the Central Ministry of Agriculture. Hon. Minister of Agriculture also has made statements in both the

Houses that whatever best could be done and whatever best could be allocated, would be done to the State of Maharashtra. But nothing substantive has come our way. At this stage, I would urge upon the hon. Agriculture Minister to release substantial funds for the State of Maharashtra as Maharashtra, Bihar and Jharkhand are the worst States which are affected due to agricultural crisis. I would like hon. Minister to adopt the suggestions and recommendations made by hon. Sharad Pawarji and Mr. D. Raja because that will go a long way in helping the farmers' community and ease the agrarian crisis not just in the State but in the entire country.

The last point that I would like to make is this. A device should be evolved by the Government of India whereby banks should be told to restructure their loans and there should not be any burden, there should not be any coercion. Some measures should be adopted so that the farmers are not pushed to the wall.

The last thing that I would like to emphasise upon is regarding the Crop Insurance Scheme. Other hon. Members also mentioned about it. There has to be some orientation programme for the farmers for the Scheme because they are not aware of it. Most of the time it so happens that banks, while lending them agricultural loan, deduct the crop insurance premium straightaway. And they are not aware of it. At the time of claims, they are not able to ...(*Time-bell rings*)... At the same time, by way of FDI, insurance sector has been opened up. Foreign companies have come but private insurance companies are not taking that burden by going into the rural areas where some kind of initiation is expected. The Crop Insurance Scheme needs to undergo a complete change. Unless that is changed, the crop insurance is not going to help the farmers and improve their condition. For that, I would request the hon. Agriculture Minister to take some immediate steps and come to the rescue of the farmers and the country. Thank you, Sir.

SHRI TIRUCHI SIVA : Sir, once again, we are having a discussion on the serious situation arising out of floods and drought in the country. Recently, I think nine States have been affected by drought and three States by floods.

The Tamil Nadu State has been severely affected by the recent rains and floods. In four or five months, we will be discussing the drought situation in our State. What is the situation? What we are doing now is only relief and remedial measures. If drought or flooding occurs in some parts of the country, as my colleague pointed out, the Centre extends some financial assistance and the States take some action. But it is not so. The method of treatment which is being given is only relieving the pain and not curing the disease. What is the permanent solution to this? We call ourselves a nation but one part of the country is affected by drought and the other

[Shri Tiruchi Siva]
part by floods. What is the way out? As many of my colleagues pointed out, it is only the interlinking of rivers – from the Ganges to the Cauvery or the Tamraparni. But, practically, it is not possible. I am not saying that. Earlier, the predecessors, who have been here from the Ministry of Water Resources, have declared in the same House that it is not feasible or possible because of the escalated cost as well as the displacement that will happen while interlinking of rivers. So, we suggest that at least the rivers in the southern States should be linked. It would bring a solution to the maximum extent possible that we are expecting.

When the DMK was in power, our leader Dr. Kalaignar evolved a new scheme for intra-linking the rivers within the States. That itself will help because it starts from the Palar, the Thenpennai, the Cauvery, the Vaigai and the Tamraparni. We mooted and started intra-linking of rivers. Before linking all the rivers, the Central Government should think of linking southern rivers, if possible. This is the remotest chance, which we have been telling for decades, because now the cost of linking all the rivers in the country is unimaginable. So, Sir, this is the first point. Second is global warming and climate change. Is it one of the reasons? The Environment Minister, when he replied here, said that the recent flood in Chennai is not due to climate change. We agree to that. Sir, global warming and climate change are not centred in India alone; it is a global issue. That has to be tackled with the cooperation and coordination of many other countries. But, now, what I suggest is that there must at least be coordination between Ministries. Drought and flood is not only the entity of the Agriculture Minister nor the Water Resources Minister. The Environment Minister should also be taken into confidence. They all should sit down and evolve a policy or evolve a solution for this. I say one thing. It is the lack of concentration or the negligence on the part of the Union Government. I don't hesitate to say that. The Cauvery Water Disputes Tribunal has already given its award and the Supreme Court has also directed that the Cauvery Management Board should be constituted whereas I have got a negative reply from the Minister. The Minister says that it is not possible. If the Cauvery Management Board is constituted, the drought situation in Tamil Nadu will not arise. We will be waiting for the water in the Cauvery. It won't be released. We will again come to the Inter-State Council. Then, we go to the Supreme Court and then to the Tribunal. The Tribunal gives an award, but nobody respects that. The Central Government also does not implement that. So, Sir, it is not the fault of the nature alone, which is the reason for all these things. The Government should also have the responsibility. ...(*Time bell rings*)... What are the reasons for floods? They say that there are too many reasons. Urban planning, lack of concentration, unauthorised construction on lakes, global warming, climate change and

many other things are there. The Minister has said in today's reply ...(*Interruptions*)... I am talking in general. ...(*Interruptions*)... I am talking in general. Why do you interrupt unnecessarily? ...(*Interruptions*)... He has mentioned some reasons which are general. It is not particular to any Government or any State. Floods occur due to the hydrological response of heavy rainfall. This should be studied very deeply. Hydrological response and its manifestations need to be assessed by local authorities; moreover, the non-climatic reasons for flooding cities and industries located in high risk locations, particularly coastal areas. ...(*Time-bell rings*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude. Five minutes are over. ...(*Interruptions*)...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, one minute please. We are discussing about a serious issue. Kindly give me one or two minutes. We are not wasting time. I don't waste words and I don't waste the time also. Areas include lack of proper urban planning, demographic pressures, improper sewage disposal and drainage systems, encroachment on lands, etc. So, it is common to the country across States. So, what Tamil Nadu has faced recently, some other States will face in the coming years. So, Sir, I would urge the Government or the Ministers concerned to sit and evolve a policy that these things should not happen. At least, we should not have a discussion so frequently. Every year and every session, we have discussion about drought or flood. So, that is not the solution. We call ourselves a developing country or a developed country. We go to various countries and discuss with them. But, what have we done? So, Sir, I would suggest that first there should be coordination between the Ministries – the Water Resources Ministry, the Agriculture Ministry and the Environment Ministry. They should sit down, discuss and evolve a policy. That only will save the future of the country. Basically, we should not forget that India is an agricultural country. If agriculture perishes, future of India will be a very big question. Population is increasing whereas food production is going down. So, we have to concentrate on that also. Thank you very much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much. Now, I have to share my problem with you. I have some more names from the Indian National Congress and the BJP. Both Parties have time. The BJP has more than ten minutes and I have two names with me. The Congress has more than 20 minutes and I have four names with me. But, these names have been given after the commencement of the discussion. ...(*Interruptions*)...

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश): सर, लिस्ट में मेरा नाम है **...(व्यवधान)...** सर, हमारा नाम पहले से है। **...(व्यवधान)...**

SHRI RAJEEV SHUKLA (Maharashtra): I will give you a solution. ...(*Interruptions*)... There are only six names left. Everybody can speak for 2-3 minutes and then, reply can be tomorrow. Reply will be tomorrow. Let the speakers be over today and reply can be tomorrow.

श्री मुख़्तार अब्बास नक़वीः ऑनरेबल डिप्टी-चेयरमैन सर, मेरी request है कि यह बहुत ही important issue है और एक-दो मिनट में मेम्बर अपनी बात नहीं कह पाते। मेम्बर्स डिटेल में बोलना चाहते हैं और उनके अच्छे सुझाव भी आ रहे हैं। हमारी request है कि जहां तक reply की बात है, अगर आज नहीं होता है तो कोई बात नहीं, जितने लोग बचे हुए हैं, वे इस पर चर्चा भी कर लें और कल ही reply हो जाएगा। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, reply tomorrow and *charcha* today.

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: Reply can be tomorrow, and the remaining Members can speak before the Minister's reply. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please understand what the hon. Minister has said. The Minister has said these Members can also speak tomorrow, and after that reply by the Minister. Do you agree with that?

श्री राजीव शुक्ल : नक़वी जी, डिस्कशन आज खत्म करा लो और मिनिस्टर का reply कल हो जाएगा। **...(व्यवधान)...**वैसे हमेशा यह परंपरा रही है। **...(व्यवधान)...**

श्री मुख़्तार अब्बास नक़वी : हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो हमारे ऑनरेबल मेम्बर्स हैं, मैं उनकी दृष्टि से कह रहा हूं कि बहुत अच्छे सुझाव आ रहे हैं। आप उनको एक मिनट या दो मिनट में मत बांधिए। आप उनको बोलने दीजिए। इसलिए हमने कहा है **...(व्यवधान)...**

श्री राजीव शुक्ल : 'मनरेगा' की बात 3 मिनट में ही हो जाती है। **...(व्यवधान)...**

श्री मुख़्तार अब्बास नक़वीः आप ऐसे कैसे गारंटी ले सकते हैं कि यह एक मिनट में खत्म करेगा? **...(व्यवधान)...**

श्री राजीव शुक्ल : अच्छा, एक काम कर लीजिए, 7 लोगों को करा लीजिए। **...(व्यवधान)...**

श्री मुख़्तार अब्बास नक़वी : इसलिए **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will give a via media. Each Member can take three minutes.

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: I have no problem. You can give three minutes to each Member. ..(*Interruptions*)..

श्री के. सी. त्यागीः सर, कितने मेम्बर्स हैं? **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Six more Members are there to speak. No new name will be added to the list. Shri Tarun Viay, three minutes only.

SHRI TARUN VIJAY (Uttarakhand): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to salute the spirit of togetherness shown by Chennai people and other people who were affected by devastating rains in Tamil Nadu. ...(*Interruptions*)...

श्रीमती विप्लव ठाकुरः सर, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में मेरा नाम है। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You come up and ask, what is this? Your name is not there. ...(*Interruptions*)... It is in the second list.

SHRI TARUN VIJAY: They forgot their differences and came together. ...(*Interruptions*)... I have not seen any demonstration in Chennai fighting with each other or fighting against the Government. They showed us that in times of distress we must forget our differences and come together to help each other. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mrs. Viplove Thakur, you are a senior Member, you should know the rule. Please behave properly. ...(*Interruptions*)... Mr. Tarun Vijay, please wait a minute. Please note that the Chair is not changing any name. In the first list which has been given to me her name is not there. That is what I have said. ...(*Interruptions*)... Don't make any allegation against the Chair.

SHRI ANAND SHARMA (Rajasthan): Nobody is making any allegation. But please hear me. Her name is there as per the 'List of Business' which has been circulated.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, she will be called.

SHRI ANAND SHARMA: She has given the notice.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If her name is there, she will be called.

SHRI ANAND SHARMA: Our party went by the concept that her name is already there.

श्रीमती विप्लव ठाकुर : सर, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में मेरा नाम है। **...(व्यवधान)...**

SHRI ANAND SHARMA: She gave it in writing.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It came after the commencement of the discussion. What can I do?

SHRI ANAND SHARMA: You call her today or tomorrow.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I told you, I am calling every Member. ...(*Interruptions*)... I do not know what the communication is.

SHRI ANAND SHARMA: There is no communication gap.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I do not know what the problem with the Congress Members is. See, I have clearly said that four names are there from the Congress Party; and two names from the BJP. Each Member would be given three minutes. That means all will be called. I have said that. The second point is Mrs. Viplove Thakur's name may be there in the notice, but there is a rule. I am going according to the rule. Her name was given after the commencement of the debate. Therefore, I can't call her name first. I will go by the rule. That is what I have said.

श्री तरुण विजय : सर, मेरा इतना time waste हो गया है, आप इसको नहीं जोड़िएगा।

Respected, Sir, I salute the spirit of togetherness shown by the common people of Chennai. They have set an example for all of us. I come from Uttarakhand and I have seen how, when catastrophe struck Kedarnath, people helped each other. People filled up their vehicles, big and small, with whatever they had, *roti, bread, dal*, to help the poor people who needed help. They showed to us that in times of distress, we must close ranks, forget our differences and help each other, instead of demonstrating against one thing or the other, or the Government. They showed to us that togetherness is the real idea of India. I salute them for the anthem of togetherness sung by the people of Tamil Nadu. I think this is an example for everyone, for people living in other parts of the country too.

Sir, it is time that we think about having a people's movement to address serious issues like encroachment of river banks, clearing of the river channels, etc., so that natural disasters don't get aggravated. This is a time when we must thank the hon. Prime Minister, Narendra Modiji, who went to Tamil Nadu, provided immediate relief by releasing money to the State. The Chief Minister of Tamil Nadu did a wonderful job too by providing all help to the people. This is not the time for blame-game. We must see to it that the people of Tamil Nadu get help and relief from everywhere.

सर, एक छोटा सा प्वाइंट है। मैं यह देखता हूँ कि जब धन, ऐश्वर्य और विलासिता में लिपटे लोग गरीबी और भुखमरी की बात करते हैं, तो किसानों की हालत कैसे सुधरेगी? किसान का बेटा आज किसान नहीं बनना चाहता है। वह किसान क्यों नहीं बनना चाहता है, क्योंकि किसान का सम्मान नहीं है। क्या राजनीतिक दल इस बात पर विचार करेंगे कि संसद में राजनीतिक दल 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत केवल किसानों को यहां प्रतिनिधि बना कर भेजें? किसानों के प्रतिनिधि नहीं मिलते हैं। जिनके हाथ, जिनके पांव खेती की मिट्टी में सने नहीं होते हैं, वे कैसे किसानों की भुखमरी और गरीबी पर बात करेंगे? ...**(समय की घंटी)**...

सर, मैं एक अंतिम प्वाइंट कहना चाहता हूँ। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से एक मांग करना चाहूँगा कि हमारे किसानों के जो पशु होते हैं, विशेष रूप से गायों, वे इस समय भुखमरी की हालत में हैं। जब वे उनको दूसरे क्षेत्रों में ले जाना चाहते हैं, तो रेल विभाग उनको अनुमति नहीं देता है। उनके डिब्बे लगवाए जाने चाहिए। वे उन्हें पार्सल वैन में भेजते हैं। पार्सल वैन में उनकी हालत और खराब हो जाती है। कामत साहब जैसे लोग कर्णाटक में काम कर रहे हैं, ...**(समय**

की घंटी)... मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि कृपया भुखमरी, अकालगस्त क्षेत्रों से गायों को अन्य क्षेत्रों में ले जाने के लिए आप रेल विभाग से विशेष प्रयास करें। धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः श्रीमती विप्लव ठाकुर। क्या वे चली गईं? वे नाराज हो गईं और चली गईं। हम क्या करें? Now, Shri Digvijaya Singh.

श्री दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, प्रकृति के साथ यदि छेड़छाड़ होगी, तो प्रकृति दंड देगी। यदि आप देखेंगे, पिछले डेढ़ साल में जिस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएँ आई हैं— भूकम्प, बाढ़, सूखा - तो शासन के जो हालात हैं, उनकी ओर प्रकृति भी ध्यान देती है, ऐसा हमारे इलाके में कहा जाता है। मूल रूप से आज जो ...**(व्यवधान)**...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः सर, मुझे लगता हैकि इनके नाम की जगह स्क्रीन पर अहमद पटेल साहब का नाम आ रहा है। आप इसको ठीक करवा दीजिए।

श्री दिग्विजय सिंहः मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ ...**(व्यवधान)**...

माननीय उपसभापति महोदय, चर्चा बाढ़ और सूखे पर है। मूल रूप से उन शहरों में बाढ़ का कारण वहां है, जहां drains और urban planning के अंतर्गत ध्यान नहीं दिया गया है। चाहे श्रीनगर का मसला हो, चाहे मुम्बई की बाढ़ का मसला हो, चाहे चेन्नई की बाढ़ का मसला हो, मूल रूप से यह urban planning failure के कारण है। इसका दूसरा कारण यह भी है कि जहां वर्षा ज्यादा होती रही है, वहां जंगल होने की वजह से पानी धीरे-धीरे नदी-नालों में आता था। जंगल कट जाने के कारण बाढ़ जल्दी आती है, पानी जल्दी बहता है, साथ में silt भी लेकर आता है। उस silt के कारण तालाबों में siltation हो रहा है और तालाब की capacity कम हो रही है। जब तालाब की कैपेसिटी कम होगी, तो आपको जल्दी पानी छोड़ना पड़ेगा। तीसरा कारण यह भी है, जैसे आज हम क्लाइमेट चेन्ज की बात करते हैं, कहीं-कहीं तो बारिश तेजी से हो रही है और कहीं-कहीं नहीं हो रही है। हमारा इतना बड़ा देश है। कहीं बाढ़ आएगी, कहीं सूखा पड़ेगा। इसलिए हर राज्य को अपने-अपने क्षेत्र में योजनाएं बनानी पड़ेंगी। हर क्षेत्र एग्रो क्लाइमेटिक स्पेसिफिक होना चाहिए। आजकल मेट डिपार्टमेंट काफी पहले से वॉर्निंग सिग्नल्स देता है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि विशेषकर वर्षा के दिनों में केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर परमानेंट कंट्रोल रूम्स होने चाहिए, ताकि मेट डिपार्टमेंट के साथ उनकी क्लोज मॉनिटरिंग हो और उसके अंतर्गत वे उन क्षेत्रों में, जहां भारी वर्षा की संभावना है, वहां वे पूर्व में ही कुछ ऐसे कदम उठा सकें, जिससे कि लाभ हो सके। चेन्नई शहर, जहां आसपास के इलाके में तालाबों की भरमार थी, धीरे-धीरे वहां के तालाबों के पास रीयल एस्टेट आने के बाद नेचुरल ड्रेन्स भी रोक ली गईं और तालाब भी भर गए, जिसकी वजह से वहां पर ऐसा हुआ। यह कहां तक सही है, यह मैं नहीं जानता और एआईडीएमके और डीएमके के विवाद में भी मैं नहीं पड़ना चाहता, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि तालाब से पानी जल्दी छोड़ने के बाद और रेगुलेटेड वॉर्निंग्स न होने की वजह से ऐसा हुआ है। कई जगह ऐसा हुआ है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि जहां तक फ्लड्स का सवाल है, इस पर ध्यान देना चाहिए।

दूसरी बात है कि आज ड्राउट प्रूफिंग की आवश्यकता है। शरद पवार साहब ने जो बात कही है, उससे मैं सहमत हूँ। हमारे देश में ऐसे कई इलाके हैं, जो ड्राउट एफेक्टेड है। उनके

[श्री दिग्विजय सिंह]

ड्राउट प्रूफिंग के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है। आज इस देश में सबसे बड़ी समस्या गिरते हुए भूजल स्तर की है। भूजल स्तर को अगर आपको पूरा करना है, तो उसके लिए अंडर ग्राउंड वाटर सर्वेज़ आपको करना पड़ेंगे। अंडरग्राउंड वाटर सर्वेज़ के साथ-साथ आपको एक्वीफर्स आइडेंटिफाई करना पड़ेंगे। हमारे यहां जो वर्षा होती है, हम उससे केवल 28 प्रतिशत ही उसके पानी का उपयोग करवा पाते हैं, 70 प्रतिशत से ज्यादा पानी सागर में चला जाता है, इसलिए इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट की आवश्यकता है और इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट के अंतर्गत जहां हमें ग्रासलैंड को भी बचाना चाहिए, पेड़ों को भी बचाना चाहिए, वहीं चीप मेथड्स को अपनाते हुए जो वर्षा का सर्फेस रन ऑफ है, जो natural aquifers ground water में हैं, उनको through dugwells through tubewells डायवर्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप natural aquifers को रीचार्ज नहीं करेंगे, तब तक आप ग्राउंड वाटर का उपयोग नहीं कर सकते। ड्राउट रेजिस्टेंट वेरायटीज की आवश्यकता है, जैसी कि इंडोनेशिया की बात कही। ...**(समय की घंटी)**...

सर, मैं दो-तीन मिनट लूंगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ड्राउट रेजिस्टेंट वेरायटीज आपकी ऑयल सीड्स, पल्सेस और फूडग्रेन्स तीनों में होनी चाहिए। यह विशेषकर उन क्षेत्रों के लिए होनी चाहिए, जहां पर कि अमूमन सूखा पड़ता है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, आपने नरेगा की बात कही है। वाकयी मैं महाराष्ट्र में जो इंप्लॉयमेंट स्कीम शुरू की गई थी, उसको यूपीए सरकार ने, हम लोगों ने लागू किया था और लागू करने के साथ-साथ अब उसमें बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। बुंदेलखंड पैकेज की यहां बात हुई है। राहुल गांधी जी के आग्रह पर आठ हजार करोड़ रुपए का बुंदेलखंड पैकेज यहां मंजूर हुआ था, लेकिन जिस उद्देश्य के साथ वह पैकेज मंजूर हुआ था, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने वह लागू नहीं किया। नरेगा के माध्यम से और ऐसे पैकेज के माध्यम से ड्राउट प्रूफिंग के लिए, ड्राउट प्रोन एफेक्टेड एरियाज के लिए डीपीएपी प्रोग्राम हुआ करता था, उस सारे को मर्ज करके नरेगा बनाया। साथ में बेकवर्ड ग्रांट्स फंड भी दिया जाता था, जिसको एनडीए की सरकार ने समाप्त कर दिया है। आज पूरे देश में आइडेंटिफाइड ड्राउट प्रोन एरियाज हैं। जो drought prone areas हैं, उनके लिए आपको स्पेशल योजनाएं बनानी पड़ेंगी और Integrated Watershed Management Programme के माध्यम से काम करना पड़ेगा। ...**(समय की घंटी)**... मैं आपसे एक अनुरोध और भी करना चाहता हूं। सौराष्ट्र में एक अंताला जी हुए हैं, जिन्होंने गांव के अंदर पानी को स्टोर करने के लिए surface water runoff की काफी योजनाएं बनाई हैं। उनसे भी हमें ज्ञान लेना चाहिए।

आज drinking water सबसे बड़ी समस्या है। Drinking water की समस्या को दूर करने के लिए, आपके ग्रामीण क्षेत्रों में जो hand pump लगते हैं, उनको भी बड़ी आसानी से recharge किया जाता है। इसके प्रयोग किए गए हैं। उसके आसपास गड्ढा खोदकर, जहां पर बरसात का surface water runoff आता है, उससे tube wells और hand pumps को recharge किया जा सकता है। आपको बाढ़ और सूखे के लिए हर राज्य में अलग-अलग area specific योजनाएं बनाने की आवश्यकता है, धन्यवाद।

श्री अनिल माधव दवे (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि समय की कमी के बीच में भी आपने हमें बोलने का अवसर दिया। मैं दो-तीन बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। हम सभी चाहते हैं कि इस देश के अन्दर किसानों की आत्महत्या रुके। हमारे देश के अन्दर प्रति 15 या 17 मिनट में एक किसान आत्महत्या करता

7.00 P.M.

है, यह मैंने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड निकाला है। इसमें किसी राजनीतिक पार्टी के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप करने की आवश्यकता नहीं है, यह हमारी कृषि व्यवस्था का दोष है। किसी भी कीमत पर किसान आत्महत्या न करें, अगर सदन और सदन के बाहर कृषि के जो विशेषज्ञ हैं, वे इस दिशा में जरा भी चिन्तन करना चाहते हैं, तो उन्हें और हमें तीन बातों पर विचार करना ही होगा। सबसे पहले हमें कृषि की लागत को घटाना होगा। आज हमने अपनी खेती की लागत को अनाप-शनाप बढ़ा दिया है। हमने लोन उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया को जितना सहज और सरल बना दिया है, उसके कारण किसानों में आवश्यक लोन के अतिरिक्त भी लोन लेने की प्रकृति बढ़ी है, जिसके कारण किसान ज्यादा से ज्यादा लोन लेता गया। जब उसे मोटर-साईकिल की जरूरत थी, तो वहां वह ट्रैक्टर लेने लगा, जब ट्रैक्टर की जरूरत थी, तो वहां उसने और चीज़ें बसा लीं, जिसके कारण धीरे-धीरे उसके ऊपर लोन बढ़ता गया। 'अमूल' इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। दूध से उत्पादित पैसे को वापस reinvest कैसे करना है, यह 'अमूल' सिखाता है। अंततोगत्वा हमें लोन वाली बात पर भी विचार करना पड़ेगा। तीसरा, हमें यह देखना होगा कि हमें अपनी पैदावार कैसे बढ़ानी है? पैदावार बढ़ाने की जो प्रक्रिया हमने पिछले 65 सालों में एडॉप्ट कर ली है, उसमें हम यह भूल गए हैं कि पैदावार देने वाला सबसे बड़ा भगवान ही है। भगवान हमें एक गेहूं के बीज के एवज में 125 से 150 गेहूं के दाने देता है। पैदावार तो भगवान बढ़ा रहा है, हमें तो अपनी कृषि का रक़बा बढ़ाना है और इसके साथ ही प्राकृतिक और आदर्श खेती की प्रक्रिया को अपनाना है।

आज हमने अमरीका का पल्लू पकड़ लिया है, जिसने हजारों एकड़ भूमि के ऊपर लिख दिया है- 'Abandoned for next 300 years'. हम अमरीका के रास्ते पर चल कर कहां जाएंगे? हमने अभी तक क्या प्रगति की है, में इसके दो उदाहरण देना चाहूंगा। जिस बैलगाड़ी के ऊपर आज हम अपना माल ढोते हैं, उसका डिज़ाइन वही 500 साल पुराना है। आजादी के 65 साल बाद भी एक तो हम बैलगाड़ी में ब्रेक नहीं लगा पाए और दूसरा बेयरिंग नहीं लगा पाए। इसका सारा श्रेय मैं उन विशेषज्ञों को देता हूं, जो स्वयं को कृषि वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ मानते हैं। किसी भी प्रान्त के अन्दर किसी बैलगाड़ी पर कोई बेयिंरग नहीं है और किसी भी बैलगाड़ी में ब्रेक नहीं है। टेक्निशियन लोगों से मेरा यह पूछना है कि यह क्यों नहीं है? इससे भी आगे जाकर मैं अब tool room पर आता हूं। जो लोग agriculture tools बनाते हैं, वे देखें कि आज भी हंसिया और निराई करने की जो खुरपी है, उसका डिज़ाइन वही है, जो 300 साल पहले हुआ करता था। क्या हम कोई नया डिज़ाइन नहीं बना पाए?

मेरा यह मत हैकि इस देश के अन्दर कृषि के लिए अलग बजट होना चाहिए। इसके लिए में कर्णाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, श्री यदुरप्पा जी का अभिवादन करूंगा कि जैसे केंद्र सरकार में रेलवे का अलग बजट होता है, उसी तरह उन्होंने कृषि की चिन्तन प्रक्रिया के लिए एक अलग बजट दिया। इस देश के अन्दर भी कृषि का एक अलग बजट होना चाहिए, कृषि पर एक पूरा का पूरा चिन्तन होना चाहिए और आवश्यकता हो तो इस सदन का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। उसमें सब को बोलने देना चाहिए कि आप कृषि के ऊपर क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। कृषि के भविष्य की नीति बनानी चाहिए। माननीय उपसभापति जी, मेरा इतना ही कहना है कि मालमू नहीं क्या दुर्भाग्य है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसके अन्दर जो कर्ता-धर्ता है, वह

[श्री अनिल माधव दवे]

साइंस का भी विशेषज्ञ है, वह एजुकेशन का भी विशेषज्ञ है, वह कृषि का भी विशेषज्ञ है और सबका विशेषज्ञ है। वैसे ही हम लोगों का भी जो वर्ग है, उसके बारे में भी ऐसा ही है कि आप उसे कोई भी काम दें, जिस दिन काम मिलता है, उस दिन वह एक महान ज्ञाता बन जाता है और उसको लगता है कि अब मुझे किसी से कुछ कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, I know everything about everything. मुझे ऐसा लगता है कि कृषि एक बहुत गम्भीर विषय है। किसी भी कीमत पर किसान को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले आत्महत्या रुकनी चाहिए। अगर हम आत्महत्या रोकना चाहते हैं, तो हमें भूमि, बीज का भंडारण, ...**(समय की घंटी)**... बीज, बीज के विषय, खाद, ट्रांस्पोर्ट, पैदावार ...**(समय की घंटी)**... दो मिनट, सर। बाकी सारी चीजें और किसान का जो फाइनेंशियल फ्लो है, उसके पास जो पैसा आने और जाने की प्रक्रिया है, जिसके बारे में श्री कुरियन ने बहुत काम किया है, उनका काम अमूल के अन्दर ...**(व्यवधान)**... सर, आप नहीं, मैं अमूल वाले कुरियन साहब की बात कर रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**... सर, उन्होंने वहां बहुत अच्छा काम किया है। जब जमीन से जुड़े हुए लोग काम करते हैं, तो उनके काम के अन्दर से जमीन की सुगंध आने लगती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कृषि को इतने हल्के में न लिया जाये। हमारा बहुत कुछ उसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं किसान के वंश से हूँ, लेकिन अभी दो साल पहले ही मैंने खेती शुरू की है, इसलिए मैं जानता हूँ। इस बार गेहूँ की बुआई मैंने स्वयं खड़े रह कर करायी है। पिछले रविवार को मैं वहां गया, तो मैं देखने गया कि वहां पानी आया या नहीं आया, क्योंकि एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि संसद में बैठने का अधिकार अगर आपको प्राप्त करना है और कृषि पर बात करनी है, तो साल में कम से कम एक फसल की बुआई से कटाई ...**(समय की घंटी)**... खुद करके देखो, तो शायद कुछ समझ में आयेगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजीव शुक्ल: उपसभापति जी, श्री के. सी. त्यागी जी द्वारा इनिशिएटेड इस डिबेट में भाग लेने और बोलने के लिए आपने मुझे जो अनुमति दी है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सर, मैं भाषण देने के बजाय राधा मोहन सिंह जी को कुछ सुझाव दूँगा। एक तो राज्य सरकारों की बात है, जो पवार साहब ने भी पहले कही, उनकी जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है, चाहे सूखा हो, बाढ़ हो या कृषि का विकास हो। हमारे यहां एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट 4 प्रतिशत हो, वह लक्ष्य हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ज्यादातर राज्य 2 से 3 प्रतिशत तक ही है, वे 3 के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। तो राज्यों को इस मामले में यह करना चाहिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कम से कम 4 प्रतिशत का ग्रोथ रेट आये। मुझे याद है कि नरसिम्हा राव जी जब प्रधान मंत्री बने, तब उन्होंने ग्रामीण विकास और कृषि के लिए सबसे ज्यादा पैसा देना शुरू किया। उसके बाद सारी सरकारों ने उसको कंटीन्यू किया। केंद्र सरकार से इस क्षेत्र के लिए इतना पैसा राज्यों को जाता है कि अगर सचमुच वह पिछले 25 सालों में लग गया होता, तो हमारे यहां सोने के गांव होते, अमेरिका और इंग्लैंड के गांव उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन वह पैसा एक्चुअली लगता नहीं है। इसके लिए मॉनिटरिंग का कोई न कोई सिस्टम होना चाहिए, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट 4 परसेंट हो और वह पैसा गांव में लगे, ताकि गांव की तरक्की हो सके। यह पैसा सचमुच लग नहीं पाता।

मेरा दूसरा सुझाव मार्केटिंग का है। अगर किसान को उसका मार्जिनल मूल्य नहीं मिलता है, जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो बड़ी मुश्किल है। मैं उनकी तरफ से आपकी यह बात मान सकता था कि अपनी कृषि पर लागत सस्ती करनी चाहिए और बैंकों से लोन नहीं लेना चाहिए, लेकिन समस्या तो यह है कि उपभोक्ता को तो वह 10 गुने दाम पर मिलता है, या तो वह उपभोक्ता को सस्ता मिल जाता। अगर किसान को किसी चीज के 5 रुपये मिलते हैं, तो उपभोक्ता उसी के लिए 50 रुपये दे रहा है, तो ये 45 रुपये कहां जा रहे हैं? ये 45 रुपये जो बीच में खा रहे हैं, उनकी खोज करनी होगी। उसका एक ही तरीका है। उन पर आप कार्रवाई तो नहीं कर सकते हैं, कितने लोगों पर कितनी कार्रवाई करेंगे। उसका एक ही तरीका है कि आप Direct Purchase Centres खोलें, 'सीधा खरीद केंद्र'। ये जो बीच में दलाल ले जाते हैं, उनके बजाय केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिल कर किसान के यहां से लें। 10 गांव पर एक खरीद केंद्र हो, वहां जाकर वह बेच दे। आप रिटेल चेन से— ये रिटेल चेंस लेने को तैयार हैं, उनसे खुद गवर्नमेंट बीच में प्रॉफिट ले और रिटेल चेंस को वह सप्लाई करा दे। रिटेल चेन से वही 50 रुपये की चीज़ उपभोक्ता को 20-25 रुपये में मिलेगी, किसान को भी 5 की जगह 10 से 15 रुपये मिलेंगे और बीच में गवर्नमेंट को भी 5 रुपये मिलेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय आपने विरोध किया था, लेकिन यह बहुत फायदेमंद चीज़ है। डायरेक्ट रिटेल सेंटर से कंज्यूमर को भी एडवांटेज है, सरकार को भी बीच में पैसा मिलेगा और किसान को 5 के बदले 10 से 15 रुपये मिलेंगे, यह आपको मेरा सुझाव है। आप खुद ही अन्तर देख लीजिए। आप साउथ एवेन्यू में एक सब्जी खरीदें, तो वह आपको कम से कम 50 रुपये प्रति किलो पड़ेगी और अगर आप आज़ादपुर मंडी के पास चले जायें, तो वही सब्जी वहां 20 रुपये प्रति किलो में मिल रही होती है। तो एक किलो पर 30 रुपये! क्या इतना भाड़ा है कि एक ही चीज़ आप आज़ादपुर मंडी के पास खरीदें, लेकिन साउथ एवेन्यू तक आते-आते प्रति किलो उसका दाम 30 रुपये बढ़ गया! कितना ही पेट्रोल-डीज़ल का खर्च बढ़ जाये, लेकिन इतना फर्क तो नहीं आना चाहिए! यह जो अनाप-शनाप बढ़ा लेते हैं, इसमें टीवी चैनल्स का भी बड़ा योगदान है। क्या होता हैकि अपनी स्टोरी बनाने के लिए अगर कोई चीज 50 रुपए किलो में बिक रही है तो बोलेगा कि टमाटर 80 रुपए किलो हो गया है, ब्याज 90 रुपए किलो हो गया है। जो बेचता है तो वह सोचता है कि हम सस्ते में बेच रहे हैं, हम तो 50 रुपए किलो में ही बेच रहे हैं जबकि टी.वी. पर आ रहा है कि 80 रुपए किलो में बिक रहा है। तो तुरन्त वह 80 रुपए किलो कर देता है। इसलिए इस मामले में आपको मार्केटिंग सिस्टम एस्टेब्लिश करना चाहिए, डॉयरेक्ट परचेज़ सेंटर्स खोलने चाहिए। मेरा दूसरा सुझाव यह है।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि जो एम.एस.पी. है, आप जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं, वह तो आप किसान का घटाते जा रहे हैं, किसान उससे तबाह हो रहा है और कंज्यूमर को, उपभोक्ता को जो मिल रहा है, वे दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो इतना गैप कैसे आ रहा है कि किसान का एम.एस.पी. कम हो रहा है और कंज्यूमर को ज्यादा दाम पर मिल रहा है? तो उसका अंतर कहां जा रहा है, यह आप पता लगाइए और इसको रुकवाइए। चौथी चीज यह कि रिवर गारलेंड तो बन नहीं सकता, नदियों को जोड़ने का काम, क्योंकि उसमें इतना पैसा लगेगा कि आपके पास उतना पैसा है ही नहीं। अटल जी भी ट्राई कर चुके और सबसे पहले इसका सुझाव के. एल. राव ने दिया था नेहरू जी के जमाने में। वह तो हो नहीं सकता, लेकिन आप एक छोटा काम कर सकते हो। असम और बिहार सबसे ज्यादा बाढ़ से परेशान हैं। वहां इतना पानी आ जाता है

[श्री राजीव शुक्ल]

कि पूछो मत। अगर उस पानी को आप ओडिशा, झारखंड और ईस्टर्न यू.पी. में बुंदेलखंड तक डॉयवर्ट कर सकें, तो उतना काम जरूर हो सकता है। छोटी सी माला की एक लड़ी बन सकती है, उतनी लड़ी आप बनवा लीजिए, पैसा भी कम लगेगा और बिहार की बाढ़ कम हो जाएगी, असम की बाढ़ कम हो जाएगी और ओडिशा, झारखंड, जो पास के राज्य हैं तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड तक वह आ सकता है। उससे आप इस समस्या में काफी मदद कर सकते हैं।

पांचवीं चीज यह है कि जो पवार साहब ने बोला, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। जब हमारी सरकार थी तब भी मैंने ही बात की थी। ...**(समय की घंटी)**... सर, बस दो-तीन सुझाव है। मनरेगा के पैसे से किसानों में खुशी है, अच्छी योजना है, लेकिन उससे ऐसेट्स नहीं बन रहे हैं। ऐसेट्स बनाने के लिए इसके पैसे को डॉयवर्ट करना चाहिए कि अगर वह पैसा मिलेगा तो उससे कहीं स्कूल बने, कहीं गांव में कम्युनिटी सेंटर बने, चाहे आंगनवाड़ी बने और अगर 10 किलोमीटर की पेरिफरी में कोई नेशनल प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें उन्हीं लोगों को काम करने के लिए भेजा जा सकता है। तो आपका इस प्रोजेक्ट पर जो टोटल खर्चा आता है, वह भी बच जाएगा। इसलिए मनरेगा के काम का जो मेन्डेट है, जरूर चेंज करें। अगर जयराम रमेश जी होते तो विरोध करते, अच्छा है, अभी वे बैठे नहीं हैं, इसलिए मैं आपको यह सुझाव दे रहा हूं, ताकि आप उसको नोट कर लें। बाढ़ के लिए शहरों के ड्रेनेज सिस्टम खराब है। चेन्नई का ड्रेनेज सिस्टम भी और मुम्बई का उससे भी ज्यादा खराब है। वह पूरा भरा पड़ा है। राज्यों से कहिए कि ड्रेनेज सिस्टम ठीक कराएं। चाहे आपकी जवाहरलाल नेहरू योजना है, उससे पैसा लगवाकर ड्रेनेज सिस्टम को ठीक कराइए, ताकि शहरों की जो वाटर लॉगिंग है, वह एकदम रुक सके, वरना बड़े मेट्रोपॉलिटन उसके चक्कर में फंस जाएंगे और फिर आप बाढ़ का मुकाबला नहीं कर पाएंगे।

मेरा आखिरी सुझाव यह है कि जो मराठवाड़ा की समस्या है, वह बहुत गंभीर है और उससे हम भी चिंतित हैं। डिप्टी चेयरमैन साहब, आप उस कमेटी के चेयरमैन हैं, इसलिए आपके लिए सुझाव है। आप सांसदों को छूट दें, एक-एक सांसद अगर एक-एक गांव एडॉप्ट कर ले, सांसद निधि से और पानी के लिए वहां पर कुछ कर दे, क्योंकि पानी का लेवल बहुत नीचे है, तो उसके लिए अगर सांसद अपनी निधि से 50-50 लाख, 25-25 लाख एक-एक गांव के लिए दे सके, तो उससे मराठवाड़ा का काफी काम हो सकता है, धन्यवाद। ...**(व्यवधान)**...

श्री के. सी. त्यागी : महोदय, जिस समय अरहर की दाल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया गया था, वह 46 रुपए किलो था, और वही जब बाजार में कंज्यूमर को खरीदनी पड़ी, वह दो सौ रुपए प्लस हो गई। जो राजीव शुक्ल जी कह रहे थे, मैं कहना चाहता हूं कि 46 रुपए किलो हमसे और दो सौ रुपए प्लस हमारे परिवार का जो बच्चा शहर में रह रहा है, उससे लिए जाते हैं, तो बीच में कौन खा रहा है? धूमिल की एक कविता है, "एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी सेंकता है, एक तीसरा आदमी और है जिस पर मेरे देश की संसद मौन है।"

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : Sir, the entire House has been seized of this matter. After such valuable suggestions which have come about and when there is little to add after Shri Sharad Pawar has spoken, being a farmer and working in the land as I do, there are critical areas that we need to address for which inter-Departmental and inter-Ministerial interventions are required. Number one, in

summers, जब आपके तालाब सूख जाते हैं, desilting of lakes and canals should take place so that storage increases, moisture in the land improves and the valuable soil, that is desilted, goes into smaller, tiny farmers' lands to refurbish and recharge their lands. So, compulsorily every summer you have to de-silt your tanks and canals so that optimal use of storage of water and increase in moisture content should happen. Secondly, of course, is the financial aspect of it, where the banks have to have a swift response system whereby we lend the farmer the money immediately. A farmer cannot wait for six months after the crop is over where he needs seed to immediately sow in his land. Thirdly, coming to Corporate Social Responsibility, industries such as in Bhadrachalam, we have Bhadrachalam Paper Board where I have virgin land on which I can grow gold. Such territories are being induced by industry to grow eucalyptus and after ten crops, Sir, I can only put brick kilns there, nothing else grows if you continue with eucalyptus cropping.

Now, Sir, coming to the most crucial aspect of agriculture, crop planning, crop planning is vital for the country at this point. We should be able to identify dry lands, irrigated lands and non-irrigated lands whereby we then incentivise the farmers where you will have pulse districts and cereal districts and you have to give alternate crops to non-irrigated crops. Now, we have tobacco growing lands in States like Andhra Pradesh and Telangana. You cannot grow anything where tobacco grows unless you irrigate the land. So, you can't tell the farmers to go on a crop holiday when they were considered kings of the golden crop and you will not give an alternate crop. What is happening to dry land agriculture? We see it withdrawing, instead of propagating more. Crop planning is going to be vital, Sir, on the water availability, on the standards that we apply and the need for feeding this nation. We cannot forget our food securities at this point whereby we incentivise crops. Now, if you don't do that, Sir, other nations like America, which are the biggest producers of corn, are now dumping in countries like ours corn and corn by-products. Do you see indigenous corn anywhere now other than American corn everywhere? And we are removing other foods which are balanced by agriculture utilities and bringing in breakfast like cornflakes and what not instead of our traditional indigenous food which are actually healthier for us to eat than others! So you know that cooking in tamarind extract actually removes fluoride from the body, but we have changed. Changing agricultural pattern impacts health on India and we have not studied that enough. Sir, is there a directory of our indigenous seeds available? For centuries, India protected her seeds. Farmers and their families hand-picked and hand-selected seeds after every crop. Today thanks to the policies of the Government, that we have lost our indigenous seeds and we are so impressed by Indonesia and other countries. We had water-resistant seed. We had drought-resistant seeds and we had indigenous seeds which actually fed and kept us healthier than we are in today's

[Shrimati Renuka Chowdhury]

current times and we have lost some of that indigenous seeds forever if we don't look out. We are losing vegetable species, we are losing pulse and cereal species which are not available anymore simply because we have not paid or invested in traditional indigenous seed banks which should be done with great urgency even today and unless we ...(*Time-bell-rings*)... water surplus land where there is rich water, you should be able to incentivise the farmer with immediate seed availability for them to be able to plant and grow those and dry land agriculture should look at that as well as the Water and Irrigation Department must go hand-in-glove. Otherwise, we will have mercury rising everywhere and we need to look into that. Thank you very much, Sir, for giving me a patient hearing.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. You raised very good points. Message from Lok Sabha.

MESSAGE FROM LOK SABHA

The National Waterways Bill, 2015

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

> "In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the National Waterways Bill, 2015, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 21st December, 2015."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

SPECIAL MENTIONS

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will take up Special Mentions.

Shri Mansukh L. Mandaviya.

Demand to explore possibility of getting full details of sender's address in ordinary posts to enable the police in identifying the culprits sending fake letters

SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA (Gujarat): Now-a-days, Police Department is receiving bogus letters about plantation of bombs in various public places and Government offices. This trend is rising very sharply. Based on such fake letters,